सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 185, नई दिल्ली । शनिवार, 14 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 हर तानाशाही का अंत होता है और अरविंद केजरीवाल तानाशाह...
06 भारत के विकास के लिए गांवों में डिजिटल विभाजन को...
08 भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 20 किलो सोना जब्त

उच्चस्तरीय आशीर्वाद प्राप्त विशेष परिवहन आयुक्त आईएएस शहजाद आलम के द्वारा जारी कुछ जनहित कार्य

संजय बाटला

1. महिला सुरक्षा के प्रति निर्भया कांड के बाद गृह सचिव के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा जारी आदेश को महिला सुरक्षा के प्रति प्रयोग ना होने देना। *आदेशः-

A. दिल्ली मे चल रहे और आगे नए आने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस/जीपीआरएस/ वीएलटीडी संयंत्र स्थापित होना। जिसके प्रति विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा परिवहन विभाग में भारत सरकार से शाखा बनाने के पैसे लेने के बाद भी प्राईवेट कम्पनी डिम्ट्स को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरु नही होने दिया।

B. दिल्ली की जनता को सुरक्षित विश्वसनीय सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए नियम कानून को ताक पर रख कर दिल्ली के अंतर राजकीय बस टर्मिनल में बाहरी प्राईवेट कंपनियों के एवम् ऑपरेटर्स के वाहनों को अंदर से वाहन में गैर कानूनी ढंग से सामान और सवारी भरने की इजाजत डीटीआईडीसी नाम की कंपनी को भारी भरकम फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किए। किसी भी राज्य में मोटर वाहन धारा/नियम/अधिनियम में स्टेज कैरीज परमिट से चालित या राज्य सरकार के निगम/निकाय द्वारा चालित वाहनों को ही स्टैंड से सवारी बिठाकर स्टेज के अनुसार स्टैंड पर उतारने और बैठाने की अनुमति है पर विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम ने आल इंडिया परमिट, सीसी परमिट एवम् बिना परमिट वाले वाहनों को जनहित का नाम लेकर वाहनों में सरकारी स्टैंड से सवारी बैठाने की इजाजत दे दी।

C. दिल्ली में चलने वाली कलस्टर और डीटीसी की बसों में सीसी टीवी कैमरे शुरू हुए बिना कम्पनी को पेमेंट करवा दी और एंटी करप्शन द्वारा जांच के लिए जब एफआईआर करने की आज्ञा मांगी तो फाइल को घुमा दिया

D. दिल्ली में वाहन जांच केंद्र में प्राईवेट कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए नया टेंडर जारी करने में देरी करवाई और उसे एक्सटेंशन पर कार्य करते रहने का मौका दिया।

E. प्राईवेट कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिना जांचे दिल्ली के सभी वाहनों को झूलझूली वाहन जांच शाखा पर भेजने और बुराड़ी जांच शाखा को बंद करने के निर्देश जारी किए।

F. अपने इच्छा अनुसार कार्य को बिना रुकावट पूर्ण करवाने के उद्देश्य से तकनीकी पदो पर अपने प्रिय गैर तकनीकी अधिकारी नियुक्त करे जिन्हे उन कार्यों के प्रति रति भर भी जानकारी नहीं थी जैसे डीटीओ हेड क्वार्टर में सख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति

G. उपायुक्त पद पर आसीन अधिकारियों से वाहन निर्माताओ और डीलरो को नियम से बाहर निजी फायदे के उद्देश्य से गलत नोटिंग करवा कर फाइल को अपने पास रोके रखना।

H. उपायुक्त पद के अधिकारियों (रामनाथन और ओम ढोले) द्वारा गोपनीय 🔑 (पासवर्ड) खोने की बात जानने के बाद भी दरकिनार करना जैसे अनगिनत जनहित के कार्य किए हैं पर उसके बाद भी **आयुक्त परिवहन, मुख्य सचिव दिल्ली और उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा द्वारा तो सवाल जवाब ही किया गया और ना ही जांच के आदेश**। अब आप समझ सकते हैं की उच्च स्तरीय आशीर्वाद प्राप्त आईएएस अधिकारी जो करे वह ही नियम वह ही कानून और वही सही.

धन्य है हमारे उच्च स्तरीय

दिल्ली मेट्रो में अब नहीं करना पड़ेगा भीड़ का सामना, डीएमआरसी ने लिया बड़ा फैसला....

दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएमआरसी ने अपनी सभी लाइनों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार और शनिवार को 84 अतिरिक्त फेरे लगेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरअसल मेट्रो में बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है। 20 अगस्त को 7749682 यात्री यात्राओं का रिकॉर्ड बना है।

संजय बाटला

नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 13 फरवरी को अधिकतम यात्री यात्रा 71,09,938 दर्ज की गई थी। पिछले एक माह में 17 बार यह रिकॉर्ड टूट चुका है। 20 अगस्त को 77,49,682 यात्री यात्राओं का रिकॉर्ड है। यात्री यात्रा की गणना एक यात्री द्वारा एक बार में अलग-अलग कॉरिडोर में की गई यात्रा के अनुसार की जाती है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएमआरसी ने अपनी सभी लाइनों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार और शनिवार को 84 अतिरिक्त फेरे लगेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। 29 इंटरचेंज स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों की सुविधा बढ़ी है। डीएमआरसी सारथी ऐप, वन दिल्ली ऐप, वाट्सऐप, पेटीएम, अमेजन पे सहित कई माध्यमों से टिकट खरीदने की सुविधा मिलने से भी मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है।

तिथि	यात्री यात्रा
20 अगस्त	77,49,682
09 सितंबर	77,16,910
10 सितंबर	75,71,124
11 सितंबर	75,50,620
12 सितंबर	73,25,403

अहमदाबाद-भुज के बीच देश की पहली वंदे भारत मेट्रो फर्राटा भरने को तैयार, क्या है खासियत

भारत में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन 16 सितंबर से चलने वाली है. सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लेस यह मेट्रो ट्रेन लोगों को छह घंटे से भी कम समय में अहमदाबाद और भुज के बीच सफर कराएगी.

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने बीते एक दशक में तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. वंदे भारत ट्रेन में तो शायद हम सभी कभी ना कभी सफर कर ही चुके होंगे. रेलवे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन 16 सितंबर को करेंगे. यह गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी. यह ट्रेन लगभग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चलने वाली मेट्रो की तरह ही होगी. हालांकि यह लंबी दूरी का सफर तक करेगी. महज 5 घंटे 45 मिनट में यह मेट्रो 334 किलोमीटर का सफर तय करेगी. यह पहला मौका है जब देश में वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में लोगों के मन में इस ट्रेन को लेकर सवाल होना लाजमी है. आइये हम आपको इसके बारे में विस्तार में बताते हैं.

ट्रेन का शेड्यूल : वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सुबह 5:50 बजे भुज से अपनी यात्रा शुरू करेगी और उसी दिन सुबह 10:50 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी. इसके बाद अपने रिटर्न ट्रिप के लिए यह अहमदाबाद से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और रात 11:10 बजे भुज पहुंचेगी. लोगों के लिए इस ट्रेन की सेवा सप्ताह में छह दिन उपलब्ध होगी. भुज-अहमदाबाद वंदे भारत मेट्रो के रूट पर कुल नौ स्टेशन होंगे. भारतीय रेलवे का कहना है कि यह ट्रेन हर स्टेशन पर करीब दो मिनट के लिए ही रुकेगी।

वंदे भारत मेट्रो की स्पीड : वंदे मेट्रो मेट्रो एक सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है जो 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. ट्रेन के डिजाइन की बात करें तो इस मेट्रो ट्रेन में 3 x 3 बेंच-टाइप सीट लगाई गई है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को आरामदायक यात्रा देना है. साथ ही विकालांग यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे मेट्रो मेट्रो के कोच में व्हीलचेयर-शौचालय उपलब्ध है.

17 सितम्बर 2024 को अवकाश की घोषणा-ईदे-ए-मिलाद- के सम्बन्ध में

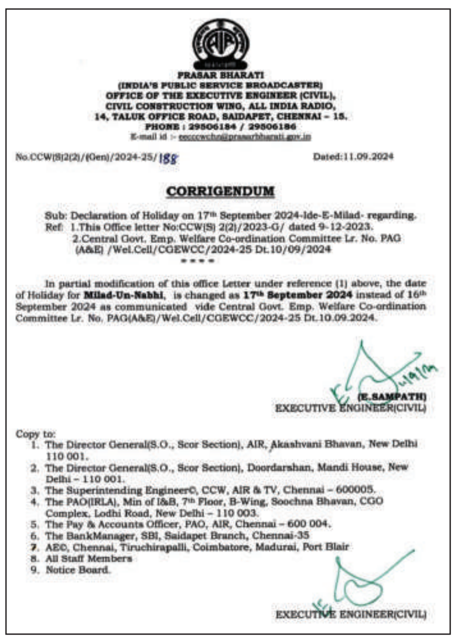
PRASAR BHARATI
(INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL),
CIVIL CONSTRUCTION WING, ALL INDIA RADIO,
14, TALUK OFFICE ROAD, SAIDAPET, CHENNAI – 15.
PHONE : 29506184 / 29506186
E-mail id :- eecccwchn@prasarbharati.gov.in

No.CCW(S)2(2)/(Gen)/2024-25/188 Dated:11.09.2024

CORRIGENDUM

Sub: Declaration of Holiday on 17th September 2024-Ide-E-Milad- regarding.
Ref: 1.This Office letter No:CCW(S) 2(2)/2023-G/ dated 9-12-2023.
2.Central Govt. Emp. Welfare Co-ordination Committee Lr. No. PAG (A&E) /Wel.Cell/CGEWCC/2024-25 Dt.10/09/2024
* * * *

In partial modification of this office Letter under reference (1) above, the date of Holiday for **Milad-Un-Nabhi**, is changed as **17th September 2024** instead of 16th September 2024 as communicated vide Central Govt. Emp. Welfare Co-ordination Committee Lr. No. PAG(A&E)/Wel.Cell/CGEWCC/2024-25 Dt.10.09.2024.

(E.SAMPATH)
EXECUTIVE ENGINEER(CIVIL)

Copy to:
1. The Director General(S.O., Scor Section), AIR, Akashvani Bhavan, New Delhi 110 001.
2. The Director General(S.O., Scor Section), Doordarshan, Mandi House, New Delhi – 110 001.
3. The Superintending Engineer©, CCW, AIR & TV, Chennai – 600005.
4. The PAO(IRLA), Min of I&B, 7th Floor, B-Wing, Soochna Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003.
5. The Pay & Accounts Officer, PAO, AIR, Chennai – 600 004.
6. The BankManager, SBI, Saidapet Branch, Chennai-35
7. AEO, Chennai, Tiruchirapalli, Coimbatore, Madurai, Port Blair
8. All Staff Members
9. Notice Board.

EXECUTIVE ENGINEER(CIVIL)

PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
कार्यकारी अभियंता (सिविल) का कार्यालय, सिविल निर्माण विंग, ऑल इंडिया रेडियो, 14, तालुक ऑफिस रोड, सैदापेट, चेन्नई 15. फोनः 29506184/29506186

ईमेल आईडीः eecccwchn@prasarbhati.gov.in

संख्या सीसीडब्लू(एस)2(2)/(सामान्य)/2024-25/188

दिनांकः11.09.2024

सही करने के लिए

विषयः 17 सितम्बर 2024 को अवकाश की घोषणा-ईदे-ए-मिलाद- के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1.इस कार्यालय का पत्र क्रमांकःCCW(S)2(2)/2023-G/दिनांक 9-12-2023. 2.केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति पत्र क्रमांकःPAG(A&E)/Wel.Cell/CGEWCC/2024-25 दिनांक 10/09/2024

उपरोक्त संदर्भ (1) के तहत इस कार्यालय के पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, मिलाद-उन-नबी के लिए अवकाश की तिथि 16 सितंबर 2024 के स्थान पर 17 सितंबर 2024 कर दी गई है, जैसा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के पत्र संख्या PAG(A&E)/Wel.Cell/CGEWCC/2024-25 दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है।

(ई. संपत) कार्यकारी अभियंता (सिविल)

कॉपीः

1. The Director General (S.O., Scor Section), AIR, Akashvani Bhavan, New Delhi 110 001.

2. महानिदेशक (एस.ओ., स्कोर अनुभाग), दूरदर्शन, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110 001।

3. अधीक्षण अभियंता, सीसीडब्ल्यू, आकाशवाणी एवं टीवी, चेन्नई-600005।

4. पीएओ (आईआरएलए), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 7वीं मंजिल, बी-विंग, सूचना भवन, सीजीओ

5. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, आकाशवाणी, चेन्नई-600004।

6. बैंक प्रबंधक, एसबीआई, सैदापेट शाखा, चेन्नई-35

7. एईओ, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, मदुरै, पोर्ट ब्लेयर 8. सभी स्टाफ सदस्य

9. नोटिस बोर्ड.

कार्यकारी अभियंता (सिविल)

कहां है आपके रूट की बस? डीटीसी का नया ऐप करेगा आपकी मदद, स्टॉप पर गाड़ी न रोकने पर होगी कार्रवाई

परिवहन विशेष न्यूज

डीटीसी बस ऐप में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अब उन्हें डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों खास सुविधा मिलने वाली है। जिससे उन्हें बस के बारे में पल-पल की जानकारी मिलेगी। जैसे आपके रूट की बस अभी कहां है कब तक आएगी। इसके अलावा ये ऐप ऐसे चालक पर भी नजर रखेगी जो बस रोके बिना ही स्टॉप के सामने से निकल जाते हैं।

नई दिल्ली। डीटीसी अपनी इलेक्ट्रिक बसों की निगरानी के लिए एक ऐप लाएगी। जिसके माध्यम से इन बसों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके लिए डीटीसी ने कुछ माह पहले टेंडर जारी किया था, जो सफल रहा है। एक कंपनी को काम मिल गया है। कंपनी एक अक्टूबर से अपना काम शुरू करेगी।

आगे चलकर इस व्यवस्था को वन दिल्ली ऐप से भी जोड़ा जा सकेगा। जिससे स्टॉप पर पहुंचने से पहले यात्रियों को बसों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। किस रूट की बस उनके बस स्टॉप पर कितने बजे आएगी और बस अभी कहां पर है, यात्री इससे रहेंगे अपडेट।

बस रोके बिना ही स्टॉप से गुजरने वाले ड्राइवरों पर होगी कार्रवाई

डिपो से बस के निकलने व बस स्टॉप पर सवारियों को बैठाने और उतारने की जानकारी अधिकारियों को मिलेगी। इसके अलावा ऐसे चालक भी पकड़ में आएंगे जो बस रोके बिना ही स्टॉप के सामने से निकल जाते हैं।

डीटीसी (DTC Bus) के बेडे़ में आ रहीं इलेक्ट्रिक बसें किलोमीटर स्कीम के तहत आ रही हैं। बसें प्राइवेट कंपनियों की हैं। डीटीसी उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। बसों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए उनकी निगरानी जरूरी है। निजी कंपनियों और डीटीसी के बीच कई मुद्दे रहेंगे।

कहां-कहां बस द्वारा नियमों का किया गया उल्लंघन, ये भी होगा नोट

मुख्य मुद्दा रहेगा कि बसें कितने किलोमीटर चलीं उसी हिसाब से कंपनी को किराये का भुगतान किया जाएगा। कितने बजे डिपो से निकली है, रास्ते में बसें कितना समय लेती हैं और कितनी बसें डिपो में पहुंची हैं, कहां-कहां बस द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया।

इस सब पर ऐप से नजर रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर बसों पर ऑनलाइन ही जुर्माने का नोटिस भी संबंधित कंपनी के पास पहुंच जाएगा। डीटीसी के पास अभी 1600 इलेक्ट्रिक बसें हैं। आने वाले समय में इन बसों को बढ़ाए जाने की संभावना है। इसे लेकर डीटीसी निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर हो गई है।

निगरानी का काम एक अक्टूबर से शुरू

डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर में बसों की निगरानी का काम क्यू टी लोड्स टेक एंड ट्रांजिट कंपनी को मिला है। कंपनी के निदेशक सिद्धार्थ जैन ने निगरानी का काम एक अक्टूबर से शुरू कर देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जिसे आने वाले समय में वन दिल्ली से जोड़ा जाएगा, जिससे बसों के आवागमन से बारे में यात्रियों को पूर्व सूचना की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।

डीटीसी बस में सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान, कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई; अब अधिकारी रोज ही करेंगे निरीक्षण

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) की बसों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी की प्रबंध निदेशक और डिपो मैनेजर प्रतिदिन 10 बसों की औचक जांच करेंगे। गंदी बसें मिलने पर सफाई से संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और अच्छी व्यवस्था बनानी है।

नई दिल्ली। बस डिपो मैनेजर प्रतिदिन 10 बसों की औचक जांच करेंगे। डीटीसी की प्रबंध निदेशक भी औचक निरीक्षण कर बसों में सफाई की जांच करेंगी। इस दौरान बस गंदी मिली तो रखरखाव करने वाली संबंधित कंपनी पर कार्रवाई होगी। वहीं चालक और परिचालक से भी सवाल जवाब किया जाएगा। बसों में साफ सफाई को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है।

वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की 4,536 बसें सड़कों पर हैं, जिसमें 2,966 सीएनजी बसें और 1,570 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) द्वारा 3,147 बसें संचालित की जा रही हैं, जिसमें 2,747 सीएनजी और 400 इलेक्ट्रिक बसें हैं।

डीटीसी की प्रबंध निदेशक करेंगी निरीक्षण

दोनों को मिला लें तो दिल्ली सरकार के बेड़े में इस समय बसों की संख्या कुल 7,683 है। डीटीसी की प्रबंध निदेशक परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त भी हैं, इस लिहाज से वह डिम्ट्स की बसों का भी औचक निरीक्षण करेंगी। विभाग की ओर से डिम्ट्स के अधिकारियों को भी बसों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। जबकि डीटीसी के डिपो मैनेजर प्रतिदिन अपने डिपो की 10 बसों का औचक निरीक्षण कर बसों की हालत देखेंगे।

अगले सोमवार से कार्रवाई को बनाया जाएगा प्रभावी

अगर सीएनजी वाली बस गंदी मिलती है तो नोटिस देकर रखरखाव करने वाली कंपनी से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत चल रहीं इलेक्ट्रिक बसें गंदी मिलती हैं तो संबंधित कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। अगले सोमवार से इस कार्रवाई को प्रभावी बनाया जाएगा।

डीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि बसों में नियमित साफ-सफाई की जाती है। मगर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे किया जा रहा है। इसका मकसद व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखना है कि जिससे जनता को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।

नाक से खून और सांस लेने में तकलीफ हो सकते हैं न्यूबोर्न बेबी में डेंग्यू के संकेत, ऐसे रखें उनका ख्याल

Dengue एक खतरनाक बीमारी है जो इस समय लगभग पूरे देश में कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां कर्नाटक में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है तो वहीं मनोरंजन जगत में भी कई सितारे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न बेबीज में डेंगू (Dengue in infants) का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में इस लक्षणों में बच्चों में इसकी पहचान कर सकते हैं।

देशभर में इस समय डेंगू का कहर जारी है। कर्नाटक में इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं, मनोरंजन जगत में भी कई सितारे डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस बीमारी से खुद को और अपने करीबियों को बचाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। खासकर छोटे और न्यूबॉर्न बेबी (Dengue In Infant) का इस मौसम में ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कमजोर इम्युनिटी होने की वजह से वह आसानी से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, गुड़गांव में पल्मोनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. प्रतिभा डोगरा से बातचीत की।

इस दौरान हमने डॉक्टर से न्यूबॉर्न बेबीज में डेंगू के वॉर्निंग साइन्स (Warning Signs Of Dengue) और इससे बचाव के कुछ तरीकों के बारे में जाना, तो आइए जानते हैं कैसे करें अपने नवजात बच्चों में डेंगू की पहचान-

डॉक्टर बताती हैं कि बच्चों में डेंगू उनके अविकसित इम्यून सिस्टम के कारण विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। जैसे-जैसे डेंगू बढ़ता है, माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी हो जाता है, ताकि समय रहते बच्चे को मेडिकल हेल्प मिल सके। न्यूबॉर्न बेबी में डेंगू के गंभीर लक्षणों में से एक अचानक, तेज बुखार है, जो 104°F (40°C) तक पहुंच सकता है और अक्सर दो से सात दिनों तक रहता है। इसके साथ-साथ, शिशुओं को चिड़चिड़ापन, भूख न लगना और थकान भी इसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

डेंगू के गंभीर लक्षण

डॉक्टर ने गंभीर डेंगू के कुछ प्रमुख वॉर्निंग्स साइन्स के बारे में भी बताया, जो निम्न हैं-

लगातार उल्टी
मसूड़ों से खून आना
नाक से खून आना
पेट में सूजन
सांस लेने में कठिनाई
बहुत ज्यादा नींद आना
ठंडी, चिपचिपी त्वचा
पल्स कमजोर होना
प्लेटलेट काउंट में गिरावट
त्वचा पर चोट या छोटे लाल धब्बे

अगर आपको अपने बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। साथ ही माता-पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बच्चा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहे और उन्हें एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाएं देने से बचें, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे करें बच्चों का डेंगू से बचाव

चूंकि छोटे बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए माता-पिता पर निर्भर होते हैं, इसलिए यहां कुछ सरल उपाय दिए गए हैं, जो शिशुओं में मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में काफी मददगार साबित होंगे।

अपने बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनाएं।

शिशु के कपड़ों पर एंटी- मॉस्किटो स्प्रे बैंड और पैच का इस्तेमाल करें।

घर में नियमित रूप से एंटी- मॉस्किटो स्प्रे करवाते रहें।

जब शिशु सो रहे हों तो मच्छरदानी का उपयोग करें।

कारों के अंदर भी स्प्रे करना याद रखें, क्योंकि आपकी गाड़ी में बहुत सारे मच्छर होते हैं।

शिशुओं की सुरक्षा के लिए उनके आसपास एंटी- मॉस्किटो तरीके अपनाएं।

अटेंशन लेडीज! अगर आप भी रोज लगाती हैं काजल, तो आंखों को हो सकते हैं 5 गंभीर नुकसान

काजल आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है। इसी वजह से सालों से ये महिलाओं की मेकअप किट का हिस्सा है। हालांकि केमिकल से बने होने की वजह से रोज काजल लगाना आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह (Kajal Side Effects) भी हो सकता है। इसलिए अगर आप रोज काजल लगाती हैं तो आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। आइए जानें काजल से हो सकने वाले नुकसान के बारे में।

नई दिल्ली। काजल महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। यह आंखों को और खूबसूरत बनाने और निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं वजहों से कई महिलाएं रोज अपनी आंखों में काजल लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कई बार आंखों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रोज काजल लगाने से आंखों को क्या नुकसान (kajal harmful effects) झेलने पड़ सकते हैं।

रोज काजल लगाने के नुकसान

इन्फेक्शन का खतरा

काजल के रोजाना इस्तेमाल से आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जब काजल आंखों के संपर्क में आता है, तो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु भी इसके जरिए आंखों के अंदर आ सकते हैं। खासकर अगर काजल पुराना हो गया है या इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर किया गया है या इसका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है। आंखों में संक्रमण होने पर रेडनेस, खुजली, जलन और पानी निकलने जैसी परेशानी हो सकती है।

आंखों की जलन

काजल में मौजूद केमिकल्स से आंखों में जलन हो सकती है। अगर काजल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा लंबे समय तक हो, तो आंखें खराब भी हो सकती हैं।

आंखों में सूखापन

रोजाना काजल लगाने से कई बार आंखों में ड्राईनेस हो सकती है। आंखों की ड्राईनेस होने पर लालिमा, जलन और धुंधला दिखाई दे सकता है।

ड्राई आई सिंड्रोम

अगर आप रोजाना काजल लगाती हैं और पहले से ही ड्राई आई सिंड्रोम से पीड़ित हैं, तो यह स्थिति और खराब हो सकती है। ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षणों में लालिमा, जलन, खुजली, धुंधला दिखाई देना और आंखों में चुभन होना शामिल है।

आंखों की रोशनी कम होना

अगर आप रोजाना काजल लगाती हैं और आंखों में संक्रमण या जलन होती है, तो यह आपकी दृष्टि को भी प्रभावित कर सकता है। आंखों में संक्रमण या जलन होने पर धुंधला दिखाई दे सकता है और आंखों की रोशनी कमजोर होने का भी खतरा रहता है।

काजल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

यदि आप रोजाना काजल लगाना चाहती हैं, तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाला काजल खरीदना चाहिए और खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें

एक अच्छे ब्रांड का काजल चुनें।

काजल की एक्सपायरी डेट की जांच करें।

काजल किसी के साथ शेयर न करें।

काजल लगाते समय हाथों को साफ रखें और काजल को छुएं नहीं।

हर रात सोने से पहले काजल साफ करके सोएं।

काजल लगाने के लिए अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करती हैं, तो इसे नियमित रूप से साफ करें।

यदि आंखों में कोई परेशानी महसूस हो, तो डॉक्टर से परामर्श लें।

समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता हैं ईद-ए-मिलाद उन नबी का पर्व : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

सभी को ईद-ए-मिलाद उन नबी पर्व की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं

इस्लाम मज़हब में ईद मिलाद उन नबी का पर्व विशेष महत्व रखता है। ईद मिलाद उन नबी के दिन पर ही हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को इतना खास माना जाता है। यह इस साल सोमवार, 16 सितंबर के दिन मनाई जाएगी।

इस पावन अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने सभी को ईद मिलाद उन नबी पर्व की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज हम ईद-ए-मिलाद उन नबी का पावन पर्व मना रहे हैं, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईश्वर ने हजरत मोहम्मद साहब को समाज में व्याप्त बुराई को खत्म करने के लिए धरती पर भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैले अंधकार और बुराइयों को खत्म करना था। हजरत मोहम्मद साहब ने मानवता को एक नई दिशा दिखाई और समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे जीवन को सही तरीके से जीना है, कैसे दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना है, और कैसे ईश्वर की इबादत करनी है। आज के दिन हमें उनके संदेश को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना चाहिए और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए। आज के दिन हमें हजरत मोहम्मद साहब को याद करना चाहिए और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

श्री खान ने आगे कहा, आज हम ईद-ए-मिलाद उन नबी का पर्व मना रहे हैं, जो हमारे समाज को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस पर्व का सामाजिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार कर सकते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस पर्व के माध्यम से, हम अपने समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। आज के दिन हमें हजरत मोहम्मद साहब के संदेश को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए।

उन्होंने कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने अपने संदेशों में समाजहित और मुस्लिमहितों के लिए बहुत कुछ दिया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन को सही तरीके से जीना है, कैसे हम दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना है, और कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और कैसे हम अपने समाज को शांति और सौहार्द से भर सकते हैं। उनके संदेशों में हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता का भी महत्व दिया गया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं। आज के दिन हमें हजरत मोहम्मद साहब के संदेशों को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए।

हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा! आखिर 75 साल पहले इसे क्यों मिला यह दर्जा

हिंदी भारत में सबसे ज्यादा और दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भाव और विचार है जिसकी मदद से लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हिंदी के इसी महत्व को बताने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Diwas 2024) मनाया जाता है। इस मौके पर जानते हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा।

हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि जज्बात है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। देश के ज्यादातर लोग संचार के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी की इसी महत्वता को बताने के मकसद से ही हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस (Hindi Diwas 2024) यानी National Hindi Day मनाया जाता है। यह दिन हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने और इसके महत्व को बताने का दिन है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाने की वजह से कई लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। हालांकि, असलियत इससे काफी अलग है।

दरअसल, हिंदी देश की राजभाषा है। 14 सितंबर, 1949 के दिन की हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो यह मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा (Hindi Not National Language) है, तो आज हिंदी दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब। साथ ही बताएंगे क्या है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर-

क्यों राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हिंदी

अगर आप भी हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा मानते हैं, तो आपको बता दें कि हिंदी ही क्या कोई भी अन्य भाषा देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। भारतीय में संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। दरअसल, आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी थी, तो संविधान सभा में 'भाषा' के विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में पक्ष में थे, तो कुछ इसके खिलाफ।

विवाद इस बात पर था कि भारत विविधताओं का देश है, जहां कआ अलग-अलग भाषाएं और बोली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किसी भी एक भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस पर लंबी चर्चा के बाद आखिरकार हिंदी को राजभाषा बनाने का फैलसा किया गया और 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर

कई लोगों को राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर कंफ्यूजन रहता है और यही वजह है कि काफी कम लोगों को दोनों में अंतर पता होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। वहीं, राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय अदालत, संसद या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आदि।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी बेल्ट के राज्यों के साथ संचार करते समय हिंदी भाषा का उपयोग करती है। वहीं, इंग्लिश सहयोगी आधिकारिक भाषा है। इस तरह भारत के संविधान के मुताबिक, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, न कि राष्ट्रीय भाषाएं।

'मेरे जीवन का एक-एक पल, खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित', जेल से बाहर आते ही बोले केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने पर भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि उनका जीवन और खून का एक–एक कतरा देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा उनका साथ दिया है।

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल संख्या दो से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने पर भारी वर्षा के बीच बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्य सभा सदस्य संजय सिंह सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कई मंत्री व विधायक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बाहर निकलने पर यहां मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोगों को आज यहां पर इतनी वर्षा में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का एक पल, खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है।

मैंने बहुत मुसीबतें झेली: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं सच्चा था। केंद्र सरकार का नाम लिए बिना इशारों इशारों में निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन्हें लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे।

मेरी ताकत सौ गुना बढ़ गई: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आया हूं और मेरा हौसले, मेरी ताकत सौ गुना बढ़ गई है। इनके जेल की मोटी मोटी दीवारें, सलाखें, मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भवगान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज तक उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, मुझे ताकत दी है, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ते दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने को काम कर रही है, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम रही है, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ूं और आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूं।

10 मई को जेल से बाहर आए थे केजरीवाल

आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अप्रेल से जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उन्हें शीर्ष अदालत से जमानत मिली थी। 10 मई को वे जमानत के बाद जेल से बाहर आए थे। जमानत की अवधि समाप्त होने पर वे दो जून को जेल पहुंचे थे। तब से वे लगातार जेल में थे।

अरविंद केजरीवाल से पूर्व आबकारी नीति मामले में राज्य सभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना की बीआरसी नेता के. कविता को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सबसे पहले संजय सिंह दो अप्रेल को रिहा हुए। इसके बाद मनीष सिसोदिया नौ अगस्त को जमानत पर बाहर निकले। इसके बाद 27 अगस्त को के कविता जमानत पर बाहर आईं।

मां ने लगाया तिलक, पिता ने थपथपाई पीठ; तीन महीने बाद घर पहुंचे केजरीवाल का हुआ भव्य स्वागत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन महीने बाद तिहाड़ से रिहा होकर घर लौटे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उनकी मां ने तिलक लगाकर और पिता ने पीठ थपथपाकर उनको आशीर्वाद दिया। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया संजय सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा ने भी उन्हें बधाई दी।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन महीने बाद शुक्रवार को तिहाड़ से बाहर आ गए। इस दौरान उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे, जहां उनके माता-पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी मां ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया तो पिता ने पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान AAP नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तथा पंजाब CM भगवंत मान और राघव चड्ढा ने गले मिलकर उन्हें बधाई दी। वहीं, जमानत पर रिहा होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया- आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आए और बाहर आते ही शेर की दहाड़ ने तानाशाह सरकार की जड़ों को हिला दिया। आज मैं और सारी लीडरशिप अरविंद जी का स्वागत करने पहुंची...आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बताने के लिए काफी है कि 'अंत में जीत सत्य की ही होती है।' सत्यमेव जयते।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न : बता दें, केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यालयों और जगह-जगह आप के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। इसके बाद शाम को केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए।

सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने से एक बात साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है : शरद पवार

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद देश भर से विपक्षी दलों के नेताओं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सभी नेता जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बधाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संविधान की जीत हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से एक बात साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसियों की पोल खुल रही है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार को सबक सीखना चाहिए कि इस तरह विपक्षी नेताओं को प्रताड़ति करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से एक बात साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। आज की लड़ाई सच्चाई के लिए थी। किसी को घटिया तरीके से बदनाम करने की साजिश लोकतांत्रिक देश में कभी सफल नहीं होगी।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत 'संविधान की जीत' है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान दें, तो जिस तरह से सरकारी एजेंसियों की पोल खुल रही है, वह भी गौर करने लायक है। जिस भेदभावपूर्ण तरीके से विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी-सीबीआई को जो फटकार लगाई है, वह भी ध्यान देने योग्य है। इससे भारत सरकार की भी बेइज्जती हो रही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी दबाव या राजनीतिक द्वेष से मुक्त रहकर काम करना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसके पहले उनके साथियों को भी जमानत मिल चुकी है। मैं

आम आदमी पार्टी के नेताओं और अरविंद केजरीवाल परिवार को बधाई देता हूं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जमानत के योग्य पाया है। यह मोदी सरकार के लिए करारा तमाचा है, जो इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में भय और आतंक का वातावरण कायम कर रही थीं। अरविंद केजरीवाल पर यह फैसला बहुत विस्तार से आया है। सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की सर्वसम्मति से यह फैसला दिया गया है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। भाजपा को इससे सबक सीखना चाहिए। मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि इस तरह विरोधी नेताओं को प्रताड़ति करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी. राजा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की जमानत का स्वागत करते हैं। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अब देखना होगा कि कानून और न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि उनकी जामनत की कुछ कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते और उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। देखना होगा कि संविधान के अनुसार यह शर्त कैसे लागू होती है। फिलहाल उन्हें जमानत मिल चुकी है और हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है।

आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी ही थी। अब यही हर केस में होगा। क्योंकि ये सारे फर्जी मामले दिल्ली के भाजपा दफ्तर में बैठकर बनाए गए थे। उन्हें पता है कि सत्ता हस्तांतरण होता रहा है। हेमंत सोरेन के केस में हाई कोर्ट का आदेश और आज अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने लायक है। यह तमाचा सिर्फ ईडी-सीबीआई और आईटी को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पड़ा है जो बैठकर ये सारी साजिशें रच रहे हैं। इससे संदेश साफ है कि भाजपा बाज आ जाए, क्योंकि कल को जब वह सत्ता में नहीं होगी तो ये एजेंसियां उसके दरवाजे पर भी दस्तक देंगी। उस समय भी हमें बुरा लगेगा। क्योंकि वेन्डेटा पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। आम आदमी पार्टी और उनकी पूरी लीगल टीम को इसके लिए बहुत बधाई।

एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक्स हैंडल पर श्सत्यमेव जयतेश लिखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को उजागर करते हुए गिरफ्तारी की टाइमिंग पर स्पष्ट और महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं, जो उल्लेखनीय हैं।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के बावजूद खुलकर फैसले ले पाएंगे केजरीवाल? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से आप को संगठन स्तर पर जरूर बड़ी राहत मिली है, परंतु सशर्त जमानत मिलने के कारण सरकार से संबंधित कार्यों को लेकर असमंजस है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हालांकि आप को दिल्ली सरकार के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। आप ने कहा है कि केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों को निर्देश देने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं ताकि जनहित में काम किया जा सके। आप ने कहा कि जल्द ही सरकार के कामकाज में बदलाव दिखाई देगा।

आप संगठन को मिली संजीवनी : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी में उत्साह है। सीधे शब्दों में कहें तो चुनावी माहौल में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाने से आप संगठन को संजीवनी मिल गई है।

हालिया चुनाव में खल रही थी केजरीवाल की कमी : हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरी पार्टी को केजरीवाल की कमी खल रही थी। मगर अब चुनाव के लिए रणनीति बनाने में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी बड़ा बल मिल सकेगा।राजनीतिक दृष्टि से ये दोनों राज्य आप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पांच महीने बाद दिल्ली में होंगे चुनाव : जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार को वहां के स्थानीय नेता देख रहे हैं, जबकि दिल्ली का पड़ोसी राज्य होने के कारण पार्टी के प्रमुख नेता हरियाणा में डेरा डाल रहे हैं। मगर केजरीवाल की कमी हर स्तर पर महसूस की जा रही थी। वहीं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपनी रणनीति मजबूती से तय कर सकेगी। ठीक पांच माह बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

जेल में रहने से कई महत्वपूर्ण कार्य रुके : बता दें कि सीएम के जेल में रहने से कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है। मनीष सिसोदिया को फिर से उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। मार्च के बाद से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं होने से सरकार के सभी महत्वपूर्ण काम लगभग ठप हैं। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव नहीं हो सका है।

शर्तें लगने से बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद कम : कार्यालय नहीं जाने और किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने की शर्त के कारण विशेषज्ञों को स्थिति में बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद कम है।

हर तानाशाही का अंत होता है और अरविंद केजरीवाल तानाशाह को झुकाने वाले व्यक्ति हैं- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए भाजपा व उसकी केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को 'पिंजरे का तोता' बनाकर रखा हुआ है। सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। कोर्ट के इस फैसले ने देश को संदेश दिया है कि अगर कोई तानाशाही चलाएगा और एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो संविधान उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा थी कि केजरीवाल जेल में रहें। इसलिए उसने ईडी मामले में बेल मिलने के तुरंत बाद सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन अब भाजपा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज हो गई है कि वह ईडी-सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। इसके लिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ईडी-सीबीआई जैसे तोता-मैना का इस्तेमाल करके बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सवाल उठता है कि यह मंशा किसकी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ गलत नहीं किया है। इसके पीछे असली मंशा भाजपा की है। भाजपा की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहें। इसलिए जब ईडी मामले में केजरीवाल बाहर आने लगे, तब उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवाया गया। यह सब कुछ बहुत सोची-समझी साजिश के तहत हुआ। सीबीआई ने केजरीवाल को किसी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें भाजपा की मंशा के तहत गिरफ्तार किया। हम लगातार यह बात कह रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है कि सीबीआई ने केवल भाजपा की मंशा को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ठीक उस समय गिरफ्तार किया, जब ईडी केस में बाहर आने वाले थे। भाजपा को इस पर थोड़ा आत्म मंथन करना चाहिए। उसे इस बात के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए कि वह ईडी-सीबीआई का इतना खुलेआम दुरुपयोग कर रही थी कि आज वह सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज हो गई।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा को देश के संविधान और बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए कि उसने किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। उसने एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाला और जब वह एक एजेंसी के झूठे

मुकदमों से छूटने वाले थे, तो दूसरी एजेंसी लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का बहुत प्यार है। आज यह बात साफ हो गई है कि जब तक लोगों का प्यार, भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद, और देश के संविधान का कवच अरविंद केजरीवाल के साथ है, तब तक अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। इस झूठ को बनाने और फैलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। देश की तानाशाही हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने और खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई के साथ झूठ का पहाड़ खड़ा किया। लेकिन पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई, फिर बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जमानत ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है।

संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई, तो 22 महीने बाद सीबीआई जागी। जिस सीबीआई ने 22 महीने पहले केजरीवाल से पूछताछ की थी, वह 22 महीने बाद जागी कि अब उसे केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। इसका मतलब यह गिरफ्तारी ईडी-सीबीआई की जांच के लिए नहीं की गई थी। उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराई गई गिरफ्तारी थी। हर तानाशाही का अंत होता है। तानाशाह झुकते हैं, उन्हें झुकाने वाला चाहिए। और वह व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, संघर्ष और अपनी निष्ठा के बदौलत दिल्ली और देश की सेवा करके अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। भाजपा उन्हें जेल में रखकर उनके हौसले नहीं तोड़ सकती है। यह आम आदमी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है। यह पूरे देश और दिल्ली के लिए भी बहुत खुशी का क्षण है। अब हम हरियाणा और दिल्ली के चुनावी रण में भाजपा को बुरी तरह पराजित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इस अभियान को बहुत मजबूती मिलेगी।

संजय सिंह ने कहा कि आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा है। ईडी-सीबीआई जैसे तोता-मैना का इस्तेमाल करके यह बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकती। इनका इस्तेमाल करके न तो वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म कर सकती है और ना ही अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को समाप्त कर सकती है। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश के उन तमाम राजनीतिक दलों और इंडिया गठबंधन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में हमारा साथ दिया।

बस में आग लगने की घटनाओं की जाँच आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ करेंगे

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा परिवहन विभाग को दिल्ली सरकार की बसों में आग लगने की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश के बाद, परिवहन विभाग के अनुरोध पर आईआईटी-दिल्ली ने मामले की जांच के लिए छह विशेषज्ञों के नाम की सिफारिश की है। समिति की अध्यक्षता मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अंजन रे करेंगे और इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के साथ-साथ ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर सहित कई विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

एक बयान में, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा ₹यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से गठित समिति मूल कारणों की पहचान करने और दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन बसों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

समिति के सदस्य

1. प्रोफेसर अंजन रे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग (अध्यक्ष)
2. प्रो. ए.के. सरोहा, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग
3. प्रो. कृष्णकांत अग्रवाल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
4. प्रो. सुमित कुमार प्रमाणिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग,
5. प्रो. सौरभ सक्सेना, सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी,
6. प्रो. राहुल गोयल, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजूरी प्रिवेंशन सेंटर (सदस्य-संयोजक)

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बसों में आग लगने की दो अलग घटनाओं के बाद त्वरित कार्रवाई की है। पहली घटना 19 मई, 2024 को हुई थी जिसमें एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई थी, जबकि दूसरी आग लगने की घटना 29 अगस्त, 2024 को क्लस्टर योजना के तहत चलने वाली सीएनजी बस में हुई थी। इन घटनाओं के आलोक में, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कारणों की जांच करने और निवारक उपायों के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एक बहु-अनुशासनात्मक समिति के गठन का निर्देश दिया था।

टर्म ऑफ़ रेफरेंस

-इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों में आग लगने के कारणों की जांच करना।

-इन घटनाओं में बस रखरखाव की भूमिका का आकलन करना।

-संभावित आग की स्थिति में ड्राइवरों को सचेत करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की सिफारिश करना।

-आपात स्थिति से निपटने के लिए ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना।

-भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय प्रस्तावित करना।

रिपोर्ट

समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर और अंतिम रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

नोएडा में 302 निवेशकों की परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी
चार लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार; सीएम योगी ने की समीक्षा

नोएडा प्राधिकरण ने ग्लोबल इनवेस्टर समिट में किए गए 452 अनुबंधों में से 302 निवेशकों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। इन परियोजनाओं से 75310 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 352993 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। ग्लोबल इनवेस्टर समिट में निवेशकों के साथ लखनऊ में प्रदेश सरकार ने अनुबंध साइन किया था। अब उनके परियोजनाओं को अब धरातल पर उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। प्राधिकरण में 452 अनुबंध साइन किए गए थे, अब तक 302 अनुबंध के तहत निवेशकों की परियोजनाओं को नोएडा प्राधिकरण धरातल पर उतारने की तैयारी को पूरा कर चुका है, जो लक्ष्य का 83.68 प्रतिशत है।

इसका लेखा जोखा मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। बता दें कि 75310 करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद 3,52,993 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

प्राधिकरण ने 452 अनुबंध सरकार के साथ साइन किए

बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए फरवरी में ग्लोबल इनवेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इसमें नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस कार्यक्रम में 103374 करोड़ के 452 अनुबंध सरकार के साथ साइन हुए।

इस निवेश के जरिये नोएडा में 441179 प्रस्तावित रोजगार देने की बात कही गई। अब अनुबंध के आधार पर निवेशकों की परियोजनाओं को धरातल पर उतरने की तैयारी को नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। उधर सरकार इन परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) यानी भूमि पूजन का भव्य समारोह कर प्रदेश के जनता को संदेश देने की तैयारी में जुट गई है।

ग्लोबल इनवेस्टर समिट के तहत नोएडा प्राधिकरण की स्थिति

कुल अनुबंध : 452
प्रस्तावित निवेश : 103374 करोड़
प्रस्तावित रोजगार : 441179
जीबीसी लक्ष्य : 90,000 करोड़
जीबीसी रेडी प्रोजेक्ट : 75310 करोड़
लक्ष्य पूरा : 83.68 प्रतिशत

अनुबंध के तहत जिन निवेशकों को जमीन का आवंटन किया गया था, उनकी परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतरने का प्रयास किया गया जा रहा है, काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। - डॉ लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण।

विभागीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर तैयारी

विभाग	जीबीसी प्रोजेक्ट	निवेश	रोजगार
औद्योगिक	157	11798	193481
संस्थागत	110	19561	95524
वाणिज्यिक	19	26501	50738
ग्रुप हाउसिंग	16	17450	13250
कुल	302	75310	352993

इन प्रमुख निवेशकों की परियोजनाएं धरातल पर उतरने जा रही

निवेशक	प्रस्तावित निवेश (करोड़)	प्रस्तावित रोजगार	जमीन अलाटमेंट (वर्गमीटर)
म 3 एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7500	14000	52035
गोदरेज प्रापर्टीज लिमिटेड	4400	3700	94310
आइकिया	4300	500	75419
अदाणी इंटरप्राइज लिमिटेड	4900	4500	73419
मैक्स डिजी इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2500	10000	108800
हल्दीराम	700	2000	66791
अग्रवाल एसोसिएट	200	1000	5999.85
यूफ्लेक्स	190	140	27557
डीएस ग्रुप	100	200	25300
कुल	**24790**	**34040**	**502046**

गाजियाबाद में 30 घंटे तक रहेगा रूट डायवर्जन, वजह है खास; देखें क्या रहेंगे वैकल्पिक मार्ग?

यूपी के गाजियाबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान रूट डायवर्जन किया जाएगा। वहीं रूट डायवर्जन होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहनों के लिए 30 घंटे का डायवर्जन प्लान बनाया गया है। पढ़िए आखिर गाजियाबाद में किन मार्गों पर कब से कब तक रूट डायवर्जन किया जाएगा ।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए हिंडन नदी और गंगनहर के पास श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान बनाया है।

ट्रैफिक पुलिस 16 सितंबर की सुबह छह बजे से मालवाहक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर देगी। मेरठ रोड पर मुरादनगर की तरफ मालवाहक वाहन बंद रहेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से वाहनों की आवाजाही होगी।

मालवाहक वाहन पर लगाई गई रोक

वहीं, जीटी रोड पर बॉर्डर से हिंडन पुल के बीच भी भारी और हल्के मालवाहक वाहन नहीं चल सकेंगे। गंगनहर कांवड़ मार्ग पर मेरठ के जानी और मुरादनगर के बीच सभी तरह के मालवाहक वाहन पर रोक लगाई गई है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, डायवर्जन 17 सितंबर की दोपहर तक लागू रहेगा।

नोएडा आते ही सीएम योगी ने दिया तोहफा, 30 साल का इंतजार होगा खत्म; दादरी से पिलखुवा तक बनेगा 30 किमी लंबा मार्ग

तीस साल के लंबे इंतजार के बाद दादरी तहसील के साठा चौरासी गांवों के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर और हापुड़ को जोड़ने वाले दादरी से पिलखुआ तक तीस किलोमीटर लंबे जर्जर मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस सड़क के बनने से साठ गांवों के लोगों को काफी फायदा होगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। दादरी तहसील क्षेत्र के साठा चौरासी का संपर्क मार्ग पिछले तीस सालों से जर्जर अवस्था में है। इस मार्ग से गुजरने वाले साठ चौरासी के गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक संगठन सड़क निर्माण के लिए कई बार मांग कर चुके हैं।

भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया के प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने सड़क निर्माण पर सहमति दे दी है। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। गौतमबुद्धनगर और हापुड़ (साठा चौरासी) को जोड़ने वाला दादरी से पिलखुआ तक तीस किमी लंबा मार्ग लगभग वर्षों से जर्जर है। इस मार्ग से रोजाना लगभग साठ गांवों के किसानों और व्यापारी व आम जनता का अवागमन रहता है।

सतेंद्र सिसोदिया ने सीएम योगी के समक्ष उठाया मुद्दा

जर्जर मार्ग से होकर गुजरना लोगों की मजबूरी बन चुका है। संबंधित विभागों को शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर लोगों में रोष बढ़ रहा था। इसे देखते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मामला उठाया था। मुख्यमंत्री मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं।

सड़क के लिए बीस करोड़ रुपये हुए थे आवंटित

सतेंद्र सिसोदिया ने बताया के दादरी से बिसाहड़ा, प्यावली, पिलखुआ मार्ग के चौड़ीकरण के लिए दो साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री ने अब इस पर सहमति दे दी है। बीस करोड़ रुपये आवंटित हो गए हैं। कुल मार्ग का निर्माण होने से साठ गांवों को लाभ मिलेगा।

GDA पॉपर्टी की नीलामी में हिस्सा लेने की बढ़ी तारीख, जल्दी करें आवेदन नहीं तो बाद में मलना पड़ेगा हाथ

गाजियाबाद शहर में सितंबर माह में ही आने वाली 20 तारीख को जीडीए अपनी व्यवसायिक और आवासीय संपत्ति की नीलामी करने वाला है। इसके लिए लोग 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें जीडीए ने 250 से अधिक संपत्तियों की नीलामी करने वाला है। पहले यह तारीख 15 सितंबर तक थी लेकिन छुट्टी होने के कारण इसे दो दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

गाजियाबाद। आगामी 20 सितंबर को जीडीए अपनी व्यवसायिक और आवासीय संपत्ति की नीलामी करेगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले इच्छुक लोग 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अवकाश के कारण बढ़ाई गई तारीख : जीडीए ने 250 से अधिक आवासीय और व्यवसायिक संपत्ति की नीलामी में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 17 सितंबर कर दी है। ताकि नीलामी में हिस्सा लेने वाले संपत्तियों की खरीद के इच्छुक खरीदार बैंक से फार्म लेकर बैंक में ही जमा करा सके। प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 14 व 15 सितंबर को अवकाश होने के कारण अब इस तिथि को बढ़ाया गया है। नीलामी में शामिल होने वाले लोग 17 सितंबर तक फार्म ड्राफ्ट और शपथ पत्र के साथ बैंक में जमा करा सकेंगे। हिंदी भवन में 20 सितंबर को संपत्तियों की नीलामी का आयोजन किया जाएगा।

जीडीए वीसी के आदेश तीसरी बार भी ताक पर : जीडीए की विभिन्न योजनाओं में रिक्त संपत्ति का विस्तृत ब्योरा जीडीए वीसी अतुल वत्स द्वारा संबंधित अनुभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से लगातार तीसरी बार मांगा गया, लेकिन किसी अनुभाग के अधिकारी व कर्मचारी ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। अब जीडीए वीसी ने शुक्रवार आज को इससे संबंधित अधिकारियों बैठक बुलाई गई है।

कुप्रबंधन से बिगड़ती स्थितियां : विजय गर्ग

फिर शहरों में बरसाती पानी की बेहतर निकासी न होने से ₹अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली में यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है, मगर वह जमीन पर उतरता नहीं दिखता। इस वर्ष फिर दिल्ली सरकार ने जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं। इनमें जल निकासी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, अधिकारियों के आपसी 'टकराव को दूर करना, जलभराव के लिए स्थायी समाधान खोजना, अतिक्रमण हटाना और निर्माण, तोड़फोड़ और डेयरी कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना शामिल है। इन कोशिशों से यह उम्मीद बनी है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे सुधार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करके जलभराव का क को रोक पाना संभव हो पाएगा।

इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बावजूद इसके, दिल्ली में कम से कम पचास पाइसक जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए। दरअसल, दिल्ली में कुप्रबंधन महज बारिश के पानी को लेकर नहीं है सड़कों पर अतिक्रमण, बेतरतीब ढंग इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना और मनमाने ढंग से कहीं भी झुग्गी बना कर रहने लग जाना जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। जनवरी में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में 1446 शहरों में दिल्ली को नब्बेवां स्थान मिलना भी इस बात की तस्दीक तस्दीक करता है कि दिल्ली में कई स्तरों पर कुप्रबंधन है, जिसका मुकम्मल समाधान निकालना जरूरी है।

बरसात दिल्ली जैसे महानगर के लिए आफत बन जाए तो इसे किसकी नाकामी माना जाएगा? घरों, दफ्तरों और राजकीय भवनों में पानी घुसना दिल्ली जैसे शहर की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जब भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की बात कही रही हो, तो कुप्रबंधन से उपजी समस्याएं विश्व मीडिया का ध्यान खींचती ही हैं। सवाल राजधानी में जलजमाव की समस्या हल होगी ? कि आखिर कब तक दरअसल, दिल्ली की अनियोजित बसावट कारण यातायात और जाम की समस्या, सड़कों घंटों पानी भरे रहना, निचली जगहों और पुलों नीचे पानी भर जाने जैसी समस्याएं अधिक हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बरसात का इंतजार करते हैं और बरसात होने जब पानी घर के अंदर घुसने लगता और राहत आफत तब्दील हो जाती है, तो दिल्ली के विकास पर सवालिया निशान लगता ही है। दिल्ली को यातायात, जल निकासी, नाले और नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन की समस्या का हल न निकाल पाने की वजह तलाशने की चाहे जितनी कोशिश की जाए, वह परवान नहीं चढ़ सकती है, जब तक इन विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में समस्या की गहराई और उससे जुड़ी संवेदना नहीं जागती।

भारत के तमाम महानगरों में यातायात, वर्षा जल निकासी और कचरा निपटान की समस्या एक जैसी है। डब्लूआरआइ इंडिया की एक शोध परियोजना के शुरुआती निष्कर्षो से मालूम होता है कि भारत के दस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और बंगलुरु) में 2000-2015 (शहर के केंद्र के दस किमी के भीतर) के बीच हुए नए नगरीय विकास कार्यों के तहत बनी 35 फीसद इमारतों का निर्माण (428 वर्ग किमी) भूजल पुनर्भरण की अधिक या अत्यधिक संभावना वाले निचले इलाकों में हुआ है। ये सभी शहर कई वर्षों से बाढ़ या डूब जैसी समस्या से जूझते नजर आते हैं।

इस साल गर्मी ने पिछले सारे रेकार्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात और गर्मी के मिजाज में बदलाव हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि एक महीने या पूरे ऋतु में जितनी औसत बरसात होनी थी वह एक या कुछ दिनों में ही हो गई। जैसे दिल्ली में 28 जून की एक हा जन को एक ही दिन में में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 1235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जाहिर है, 88 साल 24 जून, 1936 को पहले दिल्ली का रूप आज जैसा नही था। न इतने लोग थे लोग थे और न इतनी कालोनियां थीं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 128 जून का को हुई बारिश में दिल्ली में पचास जगहों पर पर विकट जलभराव के हालात देखे गए। जलभराव से निपटने के लिए दिन भर संबंधित विभागों की टीमें लगी तक भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया। पिछले साल आज रहीं. लेकिन शाम तक दिल्ली में में आई बाढ़ की याद ताजा हो आई, जब लोगों के घरों में पानी घुस गया था और उन्हें बाहर तंबुओं में शरण लेनी पड़ी थी। बरसात में जलभराव से उपजी समस्याएं और ठंड तथा गर्मी में बेघरों की बड़ी तादाद में मौत होना दिल्ली के समुचित विकास की कमी को ही नहीं बयान करता, बल्कि मानवीय स्तर पर समाज में कम होती सामाजिकता और संवेदना की कमी को भी दर्शाता है। आजादी के बाद से राजधानी के रूप में दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझती रही है। जल माफिया की मनमानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और बहुत बड़े पैमाने पर झुग्गियों के रातोंरात खड़े हो जाने जैसी घटनाएं दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी और शहर के रूप में। पहचान बनाने से रोकते रहे हैं। हर साल सर्दी और बरसात में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू, चिकनगुनिया, मौसमी बुखार, मलेरिया से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जलभराव की वजह से इन बीमारियों का फैलाव तेजी से होता है। इसलिए दिल्ली को समस्या मुक्त राजधानी के रूप में विकसित करने की जरूरत है।

जलभराव और अतिक्रमण के अलावा कूड़े-कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम महज सरकार से नहीं होगा। आम आदमी को भी अपनी आदतों, लापरवाही और गैर-जिम्मेदराना हरकतों को छोड़ना होगा। कम क्षेत्रफल में ज्यादा आबादी का बोझ ढो रही दिल्ली में हर वर्ष बढ़ते लाखों वाहन भी दिल्ली की मौजूदा सड़कों और यातायात व्यवस्था की मौजूदा हालात को बदतर करने के जिम्मेदार हैं जलभराव से ठप यातायात या जाम के हालात सड़क की क्षमता से बहुत ज्यादा वाहनों की वजह से पैदा होते है। इसलिए व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल की जगह सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग। बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जाम की वजह से दिल्ली में पर्यावरण की समस्या खतरनाक स्तर तक पहुंच पहुंच जाती है । इसलिए सड़क यातायात व्यवस्था, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली वालों को भी आगे आना होगा। फिर, दिल्ली की समस्याओं को दलगत भावना से ऊपर उठ कर देखने की जरूरत है। जब तक यह भावना नहीं आएगी कि दिल्ली हमारी है और इसकी हर समस्या को हल करने में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है तब तक दिल्ली को दुनिया की सर्वोत्तम राजधानी के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कोर चंद वाली मंडी हरजी राम वाली मलोट पंजाब -152107

अंदाज अपना अपना

हर इंसान दूसरे से जुदा होता है । कोई-कोई तो बचपन से ही बाएं हाथ से लिखता है, लेकिन उसके लिखने की रफ्तार दाएं हाथ से लिखने वालों से कम नहीं होती। ऐसे ही खब्बू बल्लेबाज भी चौके-छक्के लगाने या गेंदबाजी करने में पीछे नहीं रहते। यानी हरेक का अपना-अपना अंदाज होता है । कोई किसी से कम या पीछे नहीं होता । वह भी सही होता है और यह वाला भी । जमाना किसी को किसी दूसरे जैसा बनाने की कोशिश करे, तो भी खुद को बचाए रखना ही चाहिए। टीवी के पर्दे पर चलने वाले प्रतियोगिता आधारित कुछ 'रियलिटी शो' में प्रतियोगियों को वहां बैठे 'जज' भी आमतौर पर किसी की नकल न करने की हिदायत देते हैं और अपने ही अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। हजारों गायक खुद को किशोर कुमार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद का अपना अंदाज कायम रखना ज्यादा लंबी दौड़ का घोड़ा बनाने का दमखम रखता है ।

प्राथमिक कक्षाओं से ही शिक्षक छात्र - छात्राओं को कुंजी या सहायक - पुस्तक की मदद न लेने की सलाह देते हैं। वजह साफ है कि अगर सभी परीक्षाओं में एक ही कुंजी से उत्तर रट कर लिखेंगे, तो सभी के औसत अंक ही आएंगे। बाकियों से हट कर उत्तर लिखने वाले ज्यादा अंक हासिल करते हैं। दरअसल, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, जो रास्ता देखा - भाला और आसान लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही रास्ता अव्वल आने के लिए सही हो । भीड़ के साथ बहने के बजाय अपनी राह खुद बनानी चाहिए, ताकि हम बाकियों से अलग हो सकें। हमेशा अलग बने रहना ही कामयाबी की वजह बनता है । जैसे आंखें झपकने - मटकाने की लाजवाब अदा ने हीरो राजेश खन्ना को रातोंरात सुपर स्टार बना दिया। यह उनकी अपनी शैली थी। ऐसा पर्दे पर पहले किसी ने नहीं किया था। कोशिश करके वही नहीं करना चाहिए, जो बाकी सभी करते हैं। कुछ अलग ढूंढ़ना चाहिए, फिर करना चाहिए । जो हट कर करता है, वह दूसरों से ज्यादा लाभ कमाता है । खलील जिब्रान की एक कहानी है। एक बार बदसूरती और खूबसूरती सागर में नहाने के लिए गईं। दोनों पानी में उतरीं । बदसूरती नहाकर पहले बाहर आ गई और खूबसूरती के कपड़े पहनकर चल दी। जब खूबसूरती बाहर आई, तो घबरा गई। अपनी लाज बचाने के लिए उसे आनन-फानन जो मिला, वही पहन लिया। अब उसके शरीर पर बदसूरती के कपड़े थे। लोग कपड़ों से धोखा खाकर बदसूरती को खूबसूरती और खूबसूरती को बदसूरती समझने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने असली कपड़ों के साथ खूबसूरती का चेहरे भी देख रखा था । इसलिए बदले कपड़ों के बावजूद उसे पहचान ही लिया । इसी अपनी निजी खूबी हरेक इंसान की खूबसूरती और दमक बरकरार रहती है । दुनिया के शीर्ष उद्योगपति जाहिर करते हैं कि जब कोई कारोबारी नया विचार आता है, जिसे सभी बेहतरीन मानें, तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंकना बेहतर होता है, क्योंकि एकदम अलग-थलग और बिरले उपाय को चुनना और उसे अपने तरीके से करने- निभाने में जुट जाना कामयाब बनाता है। ऐसा करने से मुमकिन है कि मौजूदा वक्त में थोड़ी रिक्तता या दिक्कतें झेलनी पड़ें, लेकिन आने वाला दौर अत्यंत सुखद होता है ।

खुद को बेमिसाल बनाने का एक तरीका है कि अपने अलग अंदाज में जारी रहना चाहिए। हर इंसान किसी खास काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा भी उसके अंदर भर दी गई है। बावजूद इसके कुछ को ही अपनी छिपी खूबी और काबिलियत का पता होता है। जैसे पीपल के वृक्ष की विशिष्टता है कि चाहे रेगिस्तान हो या बंजर स्थल, दलदल हो या सीमेंट की पक्की दीवार, वह कहीं भी और कभी भी अपनी जड़ें जमा लेता है । वह दूसरे पेड़ों की तरह नहीं है । इसीलिए पीपल प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। हर इंसान में भी पीपल की वही जिजीविषा होनी चाहिए कि अपनी विशेष पहचान से उत्साह और जोश से भरा रहे । एक दर्शनशास्त्री की राय है कि मेरे पीछे मत चलिए, शायद मैं नेतृत्व न कर पाऊं । मेरे आगे न चलिए, शायद मैं पीछा करने में विफल रहूं। समझना चाहिए कि हर इंसान के लिए अलग-अलग जिंदगी बुनी गई है। अपने स्वभाव के अनुकूल रास्ते पर बढ़ने की जरूरत है। जरा देर से ही सही, सफलता अवश्य कदम चूमेगी।

बचपन में सुनी-पढ़ी कछुआ और खरगोश की कहानी में अब झोल या बदलाव आ चुका है। इसके घटनाक्रम में कछुआ खरगोश को सशर्त दौड़ के लिए चुनौती देता है। वह दौड़ का मार्ग अपने मुताबिक रखने को कहता है । आत्मविश्वास से भरा खरगोश झट मान भी जाता है। दौड़ के दौरान खरगोश उछलता कूदता तेजी से तय स्थान की और दौड़ता है। लेकिन उस रास्ते में एक उफनती नदी बह रही होती है, जिस वजह से बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे-धीरे चलता वहां पहुंचता है। सरलता और सहजता से नदी पार कर लेता है। आगे लक्ष्य तक पहुंच कर जीत जाता है। सीख है कि पहले अपने स्वभाव, अंदाज और ताकत को पहचानना चाहिए । फिर उसके मुताबिक काम करने से जीत जरूर मिलेगी। लेकिन खयाल रहे कि कभी भी जल्दी या हड़बड़ी में जश्न नहीं मनाना चाहिए। जब तक हमारा उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। पूर्व - परिपक्व जश्न अधिकतर निराशा में समाप्त होते हैं ।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कोर चंद वाली मंडी हरजी राम वाली मलोट पंजाब - 152107 जिला मुक्तसर

ई-रिक्शा खरीदने पर भी मिलेगा पीएम ई-ड्राइव योजना का लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

देश में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अब एक नई सब्सिडी योजना 'पीएम ई-ड्राइव स्कीम' शुरू करने का ऐलान किया है। यह देश में 9 साल से चल रही फेम सब्सिडी स्कीम की जगह लेगी। अब इसमें एक बड़ा अपडेट यह आया है कि इस योजना के तहत न सिर्फ लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकेंगे, बल्कि ई-रिक्शा खरीदने वालों के लिए भी बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया गया है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार, 12 सितंबर को कहा कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने वालों को पहले साल 25,000 रुपये और दूसरे साल 12,500 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब्सिडी योजना दो साल तक जारी रहेगी।

एल5 श्रेणी (माल परिवहन के लिए प्रयुक्त तिपहिया वाहन) के लिए पहले वर्ष 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष 25,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी।

एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर तय की जाएगी। यह 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से दी जाएगी। हालांकि, पहले साल में प्रत्येक दोपहिया वाहन के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी। दूसरे साल यह सब्सिडी आधी होकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटे हो जाएगी और तब अधिकतम लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

योजना के तहत पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के जरिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। इस पर खरीदार और डीलर के हस्ताक्षर होंगे और इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए खरीदार को पोर्टल पर सेल्फी अपलोड करनी होगी।

सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए योजना में कई कदम उठाए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी कहते हैं कि फेम-2 से हमने कई चीजें सीखी हैं। इसलिए हर छह महीने में उत्पादन की जांच की जाएगी। इससे पता चलेगा कि चीजें ठीक हैं या नहीं।

भारत में 2025 तक ईवी, प्लग-इन हाइब्रिड किए जा सकते हैं पेश : राजीव चौहान

परिवहन विशेष न्यूज

चीनी वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी इंडिया की भारतीय सहायक कंपनी 2025 से हर साल अपनी बिक्री को दोगुना करना चाहती है।बीवाईडी इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के प्रमुख राजीव चौहान ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने जा रही है और प्लग-इन हाइब्रिड पेश करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा बीवाईडी अपने टच पॉइंट्स का विस्तार करने की भी योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य अगले 6 से 8 महीनों में इसे दोगुना करना है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 2,500 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे थे। हम भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी हैं जो केवल इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है, इसलिए पिछले साल का आंकड़ा हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। इस साल यानी कैलेंडर वर्ष का दो-तिहाई हिस्सा बीत चुका है और हमने अब तक लगभग 2,000 कारें बेची हैं। हम इस साल के अंत तक शायद 3,500 से 4,000 कारें बेचेंगे, जो एक साल पहले की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 2024 में, हमारी बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत सील सेडान से आया और शेष अट्टो 3 से आया, जो एक मिड-साइज़ एसयूवी है।

उन्होंने कहा कि हम दो मुद्दों का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम 40 से 45 लाख रुपये के इलेक्ट्रिक उपकरण बाजार में ला सकते हैं। हम उस कारोबार पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें मजबूत बनाएगा। इस फैसले को लेने के लिए हमारे पास साल के अंत तक का समय है।

बीवाईडी इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के हेड राजीव चौहान ने कहा कि हम फिलहाल खुद को प्रीमियम ब्रांड मानते हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए या बड़े पैमाने पर मार्केट में उतरना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमें भारत में आम लोगों को अपने ब्रांड और इसकी बेहतरीन तकनीक के बारे में बताने के लिए बहुत काम करना होगा और तभी हम बड़े मार्केट में कारें बेच पाएंगे। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मजबूत योजना है। अभी देश के 23 शहरों में हमारी 27 डीलरशिप और 20 वर्कशॉप हैं। इनमें से करीब 75 फीसदी बड़े शहरों में और बाकी मध्यम शहरों में हैं। अगले छह से आठ महीनों में हम अपने टच पॉइंट्स की संख्या दोगुनी करके 40 से 45 शहरों तक पहुंचना चाहते हैं। यह विस्तार मुख्य रूप से मध्यम शहरों में होगा। इसके जरिए ही लोग बीवाईडी को एक ब्रांड के तौर पर जानेंगे।

उन्होंने कहा, ₹अगर हम अपने नेटवर्क को दोगुना कर रहे हैं, तो 2025 तक हमारी खुद की वॉल्यूम ग्रोथ 2.2 गुना होनी चाहिए। हमने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, लेकिन अल्पावधि में हम कुछ वर्षों तक हर साल अपनी बिक्री को दोगुना करना चाहते हैं ताकि हम उस गति के साथ अपना तालमेल बिठा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि दो-चार महीने के आंकड़ों से यह नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में गिरावट आ रही है। अगर इस साल के आठ महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय कार बाजार में विकल्पों की संख्या भी सीमित है। कल बीते बुधवार, 12 सितंबर को भी एक इलेक्ट्रिक वाहन जेएसडब्ल्यू एमजी की विंडसर पेश की गई है। हमारी पेशकश ग्राहकों को एक और विकल्प देगी। ग्राहकों को अगले साल से बड़े विकल्प मिलेंगे जब मारुति, हुंडई, किआ जैसी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन पेश करेंगी। तब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री साल 2025 में दोगुनी हो सकती है।

अगस्त 2024 में पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री में आई गिरावट, स्कूटर की बिक्री 10% बढ़ी

परिवहन विशेष न्यूज

मांग में गिरावट से डीलरों के पास इन्वेंट्री को कम करने के लिए कंपनियों ने आपूर्ति घटाई–पिछले महीने दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री नौ प्रतिशत बढ़कर 1711662 इकाई हो गई है। पिछले महीने स्कूटर की थोक बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 606250 इकाई हो गई। पिछले महीने कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 69962 इकाई हो गई जो एक साल पहले 64944 इकाई थी।

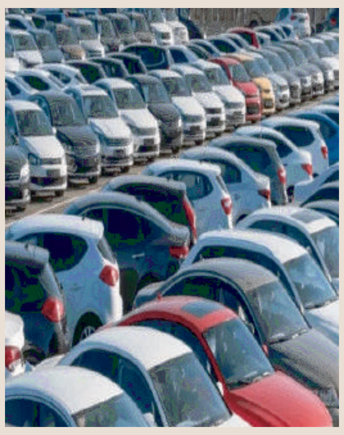

नई दिल्ली। दुनिया में सबसे बड़े वाहन बाजार में से एक इंडियन मार्केट है। सियाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त 2024 में कमी आई है। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर लगभग दो प्रतिशत घट गई। मांग में गिरावट के बीच डीलरों के पास भंडार (इन्वेंट्री) को कम करने के लिए कंपनियों ने आपूर्ति घटा दी, जिसके चलते थोक बिक्री कम हुई।

घरेलू बाजार में गिरी वाहनों की बिक्री का आंकड़ा

उद्योग संगठन सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में डीलरों के भेजी गई कुल यात्री वाहनों की खेप पिछले महीने सालाना आधार पर 1.8 प्रतिशत घटकर 3,52,921 इकाई रही। यह आंकड़ा अगस्त 2023 में 3,59,228 इकाई था।आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री नौ प्रतिशत बढ़कर 17,11,662 इकाई हो गई। यह आंकड़ा एक साल पहले इसी अवधि में 15,66,594 इकाई था।

स्कूटर की बिक्री में हुई बढ़ोतरी

पिछले महीने स्कूटर की थोक बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 6,06,250 इकाई हो गई, जो अगस्त 2023 में 5,49,290 इकाई थी। कंपनियों से डीलरों को मोटरसाइकिल की आपूर्ति पिछले महीने आठ प्रतिशत बढ़कर 10,60,866 इकाई रही, जो अगस्त 2023 में 9,80,809 इकाई थी। पिछले महीने कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 69,962 इकाई हो गई, जो एक साल पहले 64,944 इकाई थी।

देश में त्योहार शुरू होने के साथ वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-ड्राइव और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनाओं की हाल की घोषणाओं से भी बढ़ावा मिलेगा।

राजेश मेनन, महानिदेशक, सियाम

भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें जरूरी, वरना त्याग नहीं पाएंगे लोग पेट्रोल-डीजल कारों से अपना मोह

परिवहन विशेष न्यूज

इस हफ्ते जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में 10 लाख रुपये से भी कम कीमत में एमजी विंडसर ईवी लॉन्च की, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया कि यह आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कारों के बीच के अंतर को खत्म करने आई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब है, नहीं। जी हां, अगर 10 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोचते हैं, तो आप इसके अलावा अन्य 4 कारें भी गिन सकते हैं, जिनमें नई विंडसर ईवी के साथ ही एमजी कॉमेट ईवी, टाटा पंच ईवी और टिगोर ईवी शामिल हैं। डीजल-पेट्रोल कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक कारें अभी भी महंगी हैं। ऐसे में देश में ज्यादा किफायती इलेक्ट्रिक कारें लाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, जो देश के व्यापार घाटे में योगदान देता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर हम इस निर्भरता को कम कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर और पवन ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। बैटरी निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन से इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

भारत में सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन कैसे मिलें, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलना जरूरी है, ताकि इनकी कीमतें कम हो सकें। साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर इनकी कीमतें कम की जा सकती हैं। देशभर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करके लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात बैटरी तकनीक में निवेश करके बैटरी की कीमत कम करना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी कम होंगी।

ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर निकाली अपनी भड़ास

परिवहन विशेष न्यूज

कर्नाटक में ओला इलेक्ट्रिक शोरूम में आग लगने की घटना के बाद, कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके ईवी स्कूटरों के बारे में शिकायतों की बाढ़ आ गई, क्योंकि कई ग्राहकों ने उत्पाद की गुणवत्ता और सेवा के बारे में गंभीर चिंताएँ जताईं। ओला इलेक्ट्रिक उपयोगकर्ताओं ने दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर, खराब सेवा गुणवत्ता और उठाए जाने पर कंपनी की ओर से खराब प्रतिक्रिया जैसी कई शिकायतें कीं। कंपनी को अपने पोस्ट में टैग करने वाले एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने कहा, "एक महीना हो गया है और मेरा स्कूटर अभी भी सर्विस सेंटर में है। हमने इसे सिर्फ़ 40 दिन पहले खरीदा था, और यह 30 दिनों से वही पर है। यह किस तरह की सेवा है? ओला को टैग करते हुए पूछा कि आप इस समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं?"

एक अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने अपने पोस्ट में कहा, "पिछले 15 दिनों से कोलकाता में स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं। कोलकाता ज़ोन में बहुत खराब सेवा"।

कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में मंगलवार, 10 सितंबर को एक पीड़ित ओला इलेक्ट्रिक ग्राहक ने अपने नए खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन में समस्याओं को लेकर कर्मचारियों से बहस के बाद कंपनी के शोरूम में आग लगा दी। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है। कंपनी ने घटना के बाद एक बयान में कहा, ₹हम इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं और इस मामले में उचित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी उपाय करेंगे और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।"

इस बीच एक अन्य पीड़ित ओला इलेक्ट्रिक यूजर ने कहा, "मैंने इस प्लेटफॉर्म पर कई बार कॉल करके शिकायत की है, लेकिन ओला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। पीड़ति ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले शुक्रवार को एक तकनीशियन आएगा। कोई नहीं आया। ओला की ओर से कोई कॉल या मैसेज या कोई जानकारी नहीं मिली।₹ एक अन्य ओला ईवी यूजर ने पोस्ट किया, ₹ओला एस1 प्रो जेन 2 सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है।"

एक ग्राहक ने बताया कि ईवी स्कूटर की स्क्रीन अचानक बंद हो गई, जबकि वह पूरी तरह चार्ज था। ओला इलेक्ट्रिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी शिकायतों का जवाब दिया। कंपनी ने कहा, ₹हमें आपके अनुभव के बारे में सुनकर खेद है। हम इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आपसे कॉल पर जुड़ रहे हैं।₹ ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट जारी है क्योंकि यह अपने हाल के सर्वकालिक उच्च स्तर 157.40 रुपये प्रति शेयर से 30 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है।

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और टाटा मोटर्स की साझेदारी इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए 200 फास्ट-चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाताओं में से एक और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टाटा पावर की एक सहायक कंपनी) की एक सहायक कंपनी, टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारत की कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड (टाटा मोटर्स) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर की है। यह साझेदारी सभी मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों (सीवी) के लिए 200 फास्ट-चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। छोटे इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए आसान चार्जिंग समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पर्यावरण पूरक गतिशीलता समाधान प्रदान करने में किए जा रहे सहयोग का विस्तार करने के लिए कंपनी ने यह महत्वाकांक्षी कदम बढ़ाया है।

इस पहल के तहत टाटा मोटर्स और टाटा पावर टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक सीवी मालिकों के लिए विशेष चार्जिंग टैरिफ रखेंगे, जिसकी बदौलत गाड़ियों की परिचालन लागत कम होगी और ग्राहकों को मिलने वाले लाभ बढ़ेंगे। चार्जिंग नेटवर्क के नियोजित विस्तार के साथ, देश भर में इलेक्ट्रिक सीवी यूज़र्स को जल्द ही करीबन 1000 फास्ट चार्जर उपलब्ध होंगे।

टाटा मोटर्स के वाईस प्रेसिडेंट और बिज़नेस हेड - एससीवी एंड पीयू, श्री विनय पाठक ने कहा, ₹देश भर में सुविधाजनक स्थानों पर फास्ट चार्जर लगाकर इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए नयी क्रांति लाने के लिए टाटा पावर के साथ अपनी साझेदारी को मज़बूत करते हुए हमें बहुत ख़ुशी हो रही है। हमारा प्रयास विश्व स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहनों को इंजीनियर और निर्माण करने के साथ-साथ इन पर्यावरण-अनुकूल और उत्सर्जन-मुक्त वाहनों के उपयोग को सभी के लिए आसान बनाने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम विकसित करने में भी मदद करना है। यह साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहन संचालन को हरित बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करने के रास्ते भी तलाशेगी।"

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और एमडी श्री दीपेश नंदा ने कहा, ₹देश भर में सबसे बड़े ईवी चार्जिंग नेटवर्क में से एक बनाकर टाटा पावर देश भर में अपने विश्वसनीय और सुलभ चार्जिंग समाधानों के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सक्षम बना रही है। सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, बस/बेड़े और घरेलू चार्जर जैसे विविध क्षेत्रों में हम पहले से मौजूद है। एकीकृत ईवी चार्जिंग समाधान प्रदान करते हुए हम वाणिज्यिक वाहन चार्जिंग क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं। यह

सहयोग भारत भर में एक विस्तृत और विश्वसनीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रदान करके ई-मोबिलिटी को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"

टाटा पावर ने ईज़ी चार्ज के ब्रांड नाम के तहत अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, जिसमें 1,00,000 से अधिक होम चार्जर, 5,500+ सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और फ्लीट चार्जिंग पॉइंट, साथ ही 530 शहरों और कस्बों में 1100+ बस चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। इन चार्जर को हाईवे, होटलों, मॉल, अस्पतालों, कार्यालयों, आवासीय परिसरों जैसे अलग-अलग और सुलभ स्थानों पर लगाया गया है। यह ठोस प्रयास भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को सुविधाजनक बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

टाटा मोटर्स ने प्रस्तुत किया है ऐस ईवी, भारत का सबसे उन्नत इलेक्ट्रिक छोटा कमर्शियल वाहन, जिसके लिए देश भर में 150 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सेवा केंद्रों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऐस ईवी में एक उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली और 'फ्लीट एज' टेलीमैटिक्स है, जिसमें वाहन की स्थिति, स्वास्थ्य, स्थान और चालक के व्यवहार के बारे में रियल टाइम जानकारी के साथ वाहन के अपटाइम और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

भारत के विकास के लिए गांवों में डिजिटल विभाजन को पाटने की जरूरत है

विजय गर्ग

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे की कमीः ग्रामीण क्षेत्र अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से पीड़ित होते हैं, जिससे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिहार के कई हिस्सों में बिजली अस्थिर है, जिसका सीधा असर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पड़ता है।

जहां कुछ व्यक्तियों के पास नवीनतम तकनीकों तक पहुंच है, वहीं अन्य के पास बुनियादी जानकारी या संसाधनों का भी अभाव है। भारत में, यह विभाजन विशेष रूप से तीव्र है। शहरी क्षेत्र, जो देश का केवल 3% हिस्सा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान देता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 900 मिलियन से अधिक नागरिक वंचित हैं और उनके पास बैंकिंग, निवेश और ऋण तक पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे की कमीः ग्रामीण क्षेत्र अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से पीड़ित होते हैं, जिससे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिहार के कई हिस्सों में बिजली अस्थिर है, जिसका सीधा असर इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पड़ता है। गांवों में डिजिटल पहुंच को सक्षम करने के लिए इन कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। पहुंच बढ़ानाः डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने पर भी उपकरणों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर, हालांकि अपेक्षाकृत सस्ते हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के लिए महंगे हैं। सरकारी योजनाएं, जैसे छात्रों के लिए मध्य प्रदेश की मुफ्त स्मार्टफोन योजना, जरूरतमंद लोगों को किफायती या मुफ्त उपकरण प्रदान करके इस अंतर को पाटने के लिए आवश्यक हैं। जागरूकताः डिजिटल साक्षरता एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई ग्रामीण निवासी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। केरल के अक्षय कार्यक्रम जैसी पहल, जिसने डिजिटल साक्षरता को काफी बढ़ावा दिया है, उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ऐसे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, केरल अब डिजिटल साक्षरता में शीर्ष राज्यों में से एक है। आर्थिक अवसर पैदा करनाः प्रौद्योगिकी को आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक उपकरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, राजस्थान के ई-मित्र कियोस्क निवासियों को स्थानीय स्तर पर बिलों का भुगतान करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं। ये कियोस्क न केवल सेवाओं को सुलभ बनाते हैं बल्कि रोजगार भी पैदा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। यूपीएससी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अभी नामांकन करें ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने के समाधान नवोन्मेषी वितरण मॉडलः सहायक पहुंचः डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, भारत को नवोन्मेषी वितरण मॉडल की आवश्यकता है जो उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सरल बनाए और स्थानीय समुदायों के विश्वास का लाभ उठाए। सहायता प्राप्त पहुंच की अवधारणा यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय खुदरा विक्रेता, जो पहले से ही बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए व्यवसाय संवाददाता (बीसी) के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। अपनी क्षमता बढ़ाकर और उन्हें क्रेडिट, बीमा और निवेश जैसी उन्नत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर, ये स्थानीय नेटवर्क यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतिम-मील के नागरिकों के पास महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरणों तक पहुंच हो। इन सेवाओं को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए जो उपलब्धता, प्रयोज्यता, स्वीकार्यता और सामर्थ्य के सिद्धांतों का पालन करता हो। इस मॉडल को कुछ गांवों में सफलता मिली है और अब इसे पूरे देश में बढ़ाने की जरूरत है। ग्रामीण चैनलों के लिए अनुकूलित सेवाएँः इन ग्रामीण चैनलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ केवल शहरी समाधानों को अपनाने के बजाय, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां शहरी क्षेत्रों को व्यापक बीमा योजनाओं से लाभ हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोइंश्योरेंस विकल्पों से बेहतर सेवा मिलेगी। सफल उदाहरणः इस दृष्टिकोण को पहले ही सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा चुका हैदूरसंचार कंपनियां और एफएमसीजी अपनी पाउच पैकेजिंग रणनीतियों के माध्यम से, जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के छोटे बजट और उपभोग पैटर्न को पूरा करती हैं। इसी तरह, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब माइक्रोक्रेडिट, माइक्रोइंश्योरेंस और लक्ष्य-आधारित लचीली बचत योजनाओं जैसे नवीन उत्पादों को पेश करने के लिए कॉर्पोरेट बीसी के साथ सहयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए, एसबीआई का योनो प्लेटफॉर्म वैयक्तिकृत वित्तीय ऑफर प्रदान करता है। इसे ग्रामीण ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। जन निवेश, जन सुरक्षा और जन क्रेडिटः जन धन योजना जैसी पहल ने बड़े पैमाने पर समावेशन प्रयासों की क्षमता दिखाई है, और जन निवेश (लोगों का निवेश), जन सुरक्षा (लोगों की सुरक्षा) जैसे कार्यक्रमों को शुरू करने और लोकप्रिय बनाने के लिए समान रणनीतियाँ आवश्यक हैं), और जन क्रेडिट (पीपुल्स क्रेडिट)। ये पहल केवल तभी सफल हो सकती हैं यदि वे पूर्ण आर्थिक समावेशन के लिए आवश्यक क्रेडिट, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनें। गांवों को ऑनलाइन लानाः ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में ग्रामीण समुदायों को ऑनलाइन लाकर डिजिटल विभाजन को पाटने की क्षमता है। गांवों में छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाकर, ओएनडीसी उनके व्यापार के अवसरों का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर सकता है और बाजार तक पहुंच बढ़ा सकता है। यह डिजिटल समावेशन म्यूचुअल फंड उद्योग में पहले से ही स्पष्ट है, जहां टियर- II और टियर- III शहरों से हर महीने 400,000 से अधिक नए पोर्टफोलियो बनाए जा रहे हैं। यह बढ़ती प्रवृत्ति ग्रामीण आबादी की बढ़ती वित्तीय भागीदारी को उजागर करती है और ग्रामीण आर्थिक भागीदारी पर डिजिटल प्लेटफार्मों के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है। स्थानीय भाषाओं में सामग्रीः डिजिटल उपकरणों और संसाधनों को व्यापक ग्रामीण दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के लिए, स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करना महत्वपूर्ण है। Google जैसी कंपनियाँ नौ भारतीय भाषाओं में सेवाएँ प्रदान करके अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि भाषा संबंधी बाधाएँ ग्रामीण आबादी को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने से न रोकें। साइबर सुरक्षा जागरूकताः जैसे-जैसे अधिक ग्रामीण निवासी ऑनलाइन आते हैं, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के बारे में शिक्षित करने से उनकी सुरक्षा होगी क्योंकि वे तेजी से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण भरोसा कर सकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। 5जी और टेलीमेडिसिन का विस्तारः कनेक्टिविटी में सुधार और टेलीमेडिसिन जैसी उन्नत सेवाओं को सक्षम करने के लिए हर गांव में 5जी तकनीक का विस्तार आवश्यक है। बेहतर इंटरनेट पहुंच के साथ, सबसे दूरदराज के इलाके भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे चिकित्सा देखभाल अधिक सुलभ और समय पर हो जाएगी। सुरक्षित लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीकः ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल वित्तीय प्रणालियों में विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता है। लेन-देन की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करके, ग्रामीण डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में अधिक आश्वस्त हो सकते हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक अपनाने और विश्वास को बढ़ावा मिल सकता है। निष्कर्ष भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटना समावेशी विकास सुनिश्चित करने और लाखों नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करके, उपकरणों तक पहुंच बढ़ाकर, डिजिटल साक्षरता और क्रिएटिन को बढ़ाकरआर्थिक अवसरों के साथ, भारत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को काफी हद तक कम कर सकता है। यह दृष्टिकोण ₹विकसित भारत₹ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है, जहां प्रत्येक नागरिक, स्थान की परवाह किए बिना, देश की प्रगति और समृद्धि में शामिल है।

नशे से दूरी के लिए फिटनेस है रामबाण

किसी भी सभ्यता या देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है। इसलिए सरकार स्कूलों व अभिभावकों को इस विषय पर सचेत हो जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है। इसलिए विद्यालय स्तर पर माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडन्ना बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक, दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें।

शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। इस विषय पर इस कॉलम के माध्यम से पहले भी अनेकों बार अभिभावकों व विद्यालय प्रशासन को सचेत किया गया है कि अपने विद्यार्थी बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अब तो सोच कर कुछ हल निकालो। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य था। इस सबके पीछे कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों की दूरगामी सोच थी। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। नब्बे का दशक चलते ही हिमाचल प्रदेश में खेलों के लिए तत्कालीन खेल मंत्री रामलाल ठाकुर ने शुरुआती दौर में अच्छा कार्य किया था। प्रेम कुमार धूमल ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल ढांचा, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति करके खेलों को गति दी। जयराम सरकार में पहले गोविंद ठाकुर व बाद में राकेश पठानिया ने खेल मंत्री रहते हुए नयी खेल नीति दी जिसमें काफी आकर्षक नगद ईनाम रखे हैं। अब सुक्खू सरकार ने कुछ ईनामों में और सम्मानजनक बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा होता राज्य में प्रशिक्षक भी भर्ती होते क्योंकि खिलाड़ी तो प्रशिक्षक ही बनाएगा, मगर सरकार तो ठेके पर मजदूर की दिहाड़ी पर अब प्रशिक्षक व अन्य कर्मचारी नियुक्त कर रही है। जब लाखों बच्चों के लिए फिटनेस कार्यक्रम बनेगा, तो उसमें से ही फिट नागरिक प्रदेश को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है।

पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है। पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडन्ना तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कई मिनटों तक शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल व अंग को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें विद्यालय व घर पर उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम देना होगा, जो नशे से भी दूरी बनाता हो। तभी हम सही अर्थों में अपनी आगामी पीढ़ी को बचा सकते हैं।

राय

महाकवि मूसल की नारी चेतना'

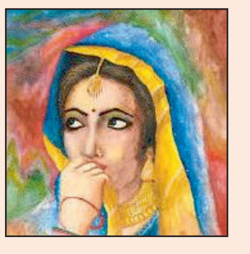

महाकवि मूसल का काव्य नारी सुलभ भावनाओं तथा उसकी समग्र चेतना से सराबोर रहा है। उनकी चेतना का आलम यह है कि नारी देखते ही कुलांचें मारने लगती है तथा घंटों तक उसमें डूबे उसी रंग से लबरेज रचनाएं लिखते रहते हैं। वे नारी को वंदनीया मानते हैं तथा खुशहाल जीवन के लिए उसका पूजन भी स्वीकार करते हैं। उनकी कविताओं में नारी का चेतना स्वर बहुत ही प्रखरता से आया है और वे उसी के संयोग तथा वियोग का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में सघनता से कर पाए हैं। उनके गीत नारी की कमर, कपोल, लटों, होंठों, चाल तथा शारीरिक सौष्ठव में डूबे नए से नए आयाम ढूंढते देखे जा सकते हैं। महाकवि मूसल की शारीरिक रचना उनके नामानुरूप मूसल के आकार की है तथा वे उसी के स्वभावगत साम्य के साथ अपना बौद्धिक कौशल भी रखते हैं। मूसल की उम्र इस समय करीब साठ वर्ष है, लेकिन नारी के मामले में वे सदैव बिलबिलाते मिलेंगे। वे अपनी पत्नी से उपेक्षा भाव बरतकर दूसरी नारियों में प्रेम के भाव तलाशते देखे जा सकते हैं। महाकवि मूसल सदैव किसी मनन-चिंतन में उलझे नारी स्तुति तथा सौंदर्योपासना में लगे रहते हैं। महाकवि मूसल से मेरा परिचय घनघोर है तथा वे जब तब अपनी कोमल कविताएं मुझ पर पेलते रहे हैं। उनका दर्द एक है, लेकिन उसे उन्होंने गाया हजारों तरह से है। वे अपने जीवन में नारी को ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा मानते हैं कि यदि उन्हें एक नारी की संगत मिल जाए तो वे कविता में क्रांति कर सकते हैं। लेकिन इस देश की नारियां उन्हें अभी क्रांति का मौका ही नहीं दे रही हैं।

जब वे उनकी प्रशंसा में कविता लिखते हैं तो वे उस समय उनका सान्निध्य चाहते हैं। इसी कारण वे उनकी धर्मपत्नी से उपेक्षित हो गए तथा आज वे इसी दर्दे दिल को लिए विविध आयामी सृजन के प्रति समर्पित हैं। पत्नी को वे पूरे दिन में तीन हजार गालियां निकालते हैं तथा दूसरी अनाम प्रेमिका के लिए अपने जीवन की तमाम मिठास को उंडेल देते हैं। हालांकि उनकी कविता में उलाहना शैली ज्यादा सघनता से उभरी है। लेकिन वे अगली कविता में अपना बैलेंस बना लेते हैं और नारी चेतना का स्वर बराबर बनाए रखते हैं। यदि उन्हें नारी सुलभ हो जाए तो कविता लिखना भूल जाते हैं। यही वजह है कि उनकी कविताओं का स्वर वियोग पर ज्यादा केन्द्रित रहा है। नारी वियोग के कारण ही वे हजारों हजार कविताएं आज हिन्दी साहित्य संसार को सौंप चुके हैं। उनकी कविताएं नारी अंगों की सुंदरता तथा उनके लिए नायाब उपमाएं ढूंढने में नूतनता के साथ सामने आई हैं। सुना है पच्चीस वर्ष की आयु में कोई नारी उनके जीवन में आई थी, वह भी केवल दो घंटे के लिए। तब से आज तक घरवाली को भूल उसकी स्मृति को यादों में संजोये काव्य सृजन के प्रति पूरे मनोयोग से जुड़े रहे हैं। महाकवि मूसल की रचनाएं हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि बन सकती हैं, यदि कोई आलोचक आगे आकर अपना समय बरबाद करने की कूवत रख सकता हो तो। वे अपने मूल्यांकन के प्रति भी कभी चिंतित नहीं रहे हैं। वे सदैव अनाम नायिका के नाम ढेर सारे उपालंभ भेजते रहते हैं और वह है कि जालिम भूले मन से भी उन्हें याद नहीं कर पाई है।

राहुल गांधी की सत्ता के लिए व्यग्रता और नेहरु

इस बार राहुल गान्धी भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इस वाक्य को एक दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि इस बार कुछ देशी-विदेशी शक्तियां राहुल गान्धी को आगे करके, उनकी आड़ में अपनी व्यक्तिगत या अन्य प्रकार की स्वार्थ सिद्धि प्राप्त करना चाहती थीं। इसके लिए उन सब ने मिल कर पूरा जोर भी लगाया। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी योजना या इच्छा पूरी नहीं हुई। वैसे केवल स्पष्टीकरण के लिए राहुल गान्धी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे देशी और विदेशी ताकतों का उद्देश्य अलग भी होता है। देशी शक्तियां या फिर वे लोग जो राहुल गान्धी को घेरे हुए हैं, उनका स्वार्थ तो ज्यादा से ज्यादा उतना ही होता है कि राहुल प्रधानमंत्री होंगे तो सत्ता में कुछ हिस्सा उनको भी नसीब होगा। इसलिए इसको व्यक्तिगत स्वार्थ ही कहा जा सकता है। लेकिन विदेशी शक्तियों का मामला दूसरा है। उन्होंने भारत में सत्ता प्राप्त नहीं करनी, लेकिन उन्हें भारत को कमजोर करना है ताकि वह विश्व राजनीति और सभ्यताओं के संघर्ष में झांकने की भी हिम्मत न करे। इसके लिए अमरीका व कनाडा सरकार पिछले कुछ दशकों से कार्यरत हैं। इन दोनों देशों में पंजाब के कुछ लोगों को भारत के खिलाफ संगठित किया जा रहा है। भारतीय दूतावासों पर हमले होते हैं। इंदिरा गान्धी के हत्यारों को महिमामंडित करते हुए सार्वजनिक झांकियां निकाली जाती हैं। भारत को तोडन्ने के संकल्प लिए जाते हैं। उत्तरी अमरीका की सरकारें इन सभी भारत विरोधी शक्तियों को प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता देती हैं। उत्तरी अमरीका के इन देनों देशों की सांस्कृतिक, मज़हबी और राजनीतक पूंछ इंग्लैंड से जुड़ी रहती है, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशों को संगठित करके ही इन देशों का गठन हुआ था।

अपने समय में इंग्लैंड सरकार भी, देश छोडन्ने से पहले भारत को विभाजित करने वाली ताकतों को संगठित कर रही थी। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना उसके मोहरे बने हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना देश को विभाजित नहीं किया जा सकता। अन्ततः कांग्रेस इंग्लैंड के माऊंटबेटन और श्रीमती माऊंटबेटन के चंगुल में फंस ही गई और उसने बाकायदा दिल्ली में पार्टी की विशेष बैठक बुला कर 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरु की उम्र 57 साल के आसपास थी। बहुत से इतिहासकार आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर खान अब्दुल खान के सख्त विरोध के बावजूद नेहरु भारत विभाजन के पक्ष में कैसे खड़े हो गए? इसका उत्तर नेहरु ने स्वयं ही परोक्ष रूप से दिया है। उनका कहना था कि यदि हम भारत विभाजन के लिए सहमत न होते तो बीस-पच्चीस साल तक और संघर्ष करना पड़ता, जेलों में जाना पड़ता, लेकिन हमारी उम्र इतनी हो गई थी कि इतने लम्बे काल तक संघर्ष करना सम्भव नहीं था। यानी तब तक नेहरु की उम्र लगभग 90 साल की हो जाती। देश बंटने से भी बच जाता और आजाद भी हो जाता, लेकिन 90 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री नेहरु न हो पाते, कोई दूसरा कांग्रेसी होता, यह नेहरु को स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने सत्ता की खातिर देश विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाबा साहिब अंबेडकर कांग्रेस की या नेहरु की इस मंशा को शुरू में ही समझ गए थे, इसलिए उन्होंने दशकों पहले कह दिया था कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के लिए लड़ रही है। लगता है इतिहास आज फिर अपने आपको दोहराता हुआ उसी मोड़ पर पहुंच गया है। 2004 के आम चुनाव में भाजपा की पराजय हुई और कांग्रेस ने डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। वे 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। कहा जाता है, उनकी सरकार में सत्ता व नीति के सूत्र सोनिया माईनो गान्धी के पास रहते थे।

जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय राहुल गान्धी की उम्र 32-33 साल के आसपास थी। तब इस राज परिवार को स्वयं ही लगा होगा कि इतनी कम उम्र में भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री बनना राहुल गान्धी के लिए सम्भव नहीं होगा। इटली होता तो अलग बात थी। उसके बाद मौका 2009 में आया। उस समय राहुल भी 37 साल के हो गए, लेकिन यह उम्र भी कम ही थी। इसलिए मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाए रखना श्रेयस्कर माना गया। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि फिलहाल राहुल गान्धी मंत्रीपद ले लें ताकि उन्हें प्रशासन का अनुभव भी हो जाए। लेकिन मंत्री बनना शायद इस परिवार को अपमानजनक लगा होगा। मनमोहन सिंह जी ने तो यहां तक भी कह दिया था कि जब मुझे कहा जाएगा, मैं राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ दूंगा। लेकिन मात्र 37 साल की उम्र आड़े आ रही थी। इस राज परिवार का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि जब राज परिवार को लगा कि 2014 में राहुल गान्धी 44 साल के वयस्क हो जाएंगे और प्रधानमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी कर दी जाएगी (उनके पिता 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे), तब भारत ने भाजपा को जिता ही नहीं दिया, कांग्रेस को 543 सीटों वाली लोकसभा में महज 44 सीटों पर पहुंचा दिया। लेकिन तभी से राज परिवार किसी भी तरह देश की सत्ता पर कब्जे के लिए व्यग्र हो गया।

वर्ष 2019 में राहुल गान्धी की उम्र पचास के आसपास पहुंच गई, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 44 से बढ़ कर पचास-पचपन से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। वर्ष 2024 तक आते-आते राज परिवार की सत्ता प्राप्ति के लिए व्याकुलता इतनी बढ़ी की मुस्लिम लीग तक से समझौता कर लिया। केजरीवाल तक को नमन किया। राहुल गान्धी की उम्र पचपन को छू गई, लेकिन कांग्रेस सांसदों की संख्या सौ को नहीं छू पाई। इतिहास 1947 के मोड़ पर ही पहुंच गया है। उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरु की उम्र 57 साल की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए लार्ड माऊंटबेटन और श्रीमती माऊंटबेटन के मोहरे बन कर देश विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। अब उन्हीं के वंशज राहुल गान्धी उम्र के उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं। वर्ष 2029 को जब अगले लोकसभा चुनाव होंगे, तो उनकी उम्र साठ साल के आसपास हो जाएगी। राज परिवार में भूकम्प आ रहा है। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गान्धी अमरीका जाकर सिखों को बता रहे हैं कि भारत में उनकी पगड़ी, कड़ा और गुरुद्वारा संकट में हैं। भारत को तोडन्ने वाली तमाम देशी-विदेशी ताकतों ने राहुल के इस कथन को उदाहरण बना लिया है। सत्ता की व्यग्रता में कांग्रेस देशी और विदेशी शक्तियों का मोहरा बन रही है। इंग्लैंड का स्थान अमरीका और कनाडा ने ले लिया है। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि आज दिल्ली में माऊंटबेटन नहीं है। ऐसी देशी-विदेशी शक्तियों के इरादे विफल करने के लिए, लगता है भारत की जनता ने यह तय कर लिया है कि कम से कम केंद्र में तो एनडीए की सरकार ही रखनी है।

कुप्रबंधन से बिगड़ती स्थितियां

फिर शहरों में बरसाती पानी की बेहतर निकासी न होने से ₹अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली में यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है, मगर वह जमीन पर उतरता नहीं दिखता। इस वर्ष फिर दिल्ली सरकार ने जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं। इनमें जल निकासी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, अधिकारियों के आपसी 'टकराव को दूर करना, जलभराव के लिए स्थायी समाधान खोजना, अतिक्रमण हटाना और निर्माण, तोड़फोड़ और डेयरी कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना शामिल है। इन कोशिशों से यह उम्मीद बनी है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे सुधार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करके जलभराव का क को रोक पाना संभव हो पाएगा।

इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बावजूद इसके, दिल्ली में कम से कम पचास पाइसक जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए। दरअसल, दिल्ली में कुप्रबंधन महज बारिश के पानी को लेकर नहीं है सड़कों पर अतिक्रमण, बेतरतीब ढंग इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना और मनमाने ढंग से कहीं भी झुग्गी बना कर रहने लग जाना जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। जनवरी में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में 1446 शहरों में दिल्ली को नब्बेवां स्थान मिलना भी इस बात की तस्दीक तस्दीक करता है कि दिल्ली में कई स्तरों पर कुप्रबंधन है, जिसका मुकम्मल समाधान निकालना जरूरी है।

बरसात दिल्ली जैसे महानगर के लिए आफत बन जाए तो इसे किसकी नाकामी माना जाएगा? घरों, दफ्तरों और राजकीय भवनों में पानी घुसना दिल्ली जैसे शहर की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जब भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की बात कही रही हो, तो कुप्रबंधन से उपजी समस्याएं विश्व मीडिया का ध्यान खींचती ही हैं। सवाल राजधानी में जलजमाव की समस्या हल होगी ? कि आखिर कब तक दरअसल, दिल्ली की अनियोजित बसावट कारण यातायात और जाम की समस्या, सड़कों घंटों पानी भरे रहना, निचली जगहों और पुलों नीचे पानी भर जाने जैसी समस्याएं अधिक हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बरसात का इंतजार करते हैं और बरसात होने जब पानी घर के अंदर घुसने लगता और राहत आफत तब्दील हो जाती है, तो दिल्ली के विकास पर सवालिया निशान लगता ही है। दिल्ली को यातायात, जल निकासी, नाले और नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन की समस्या का हल न निकाल पाने की वजह तलाशने की चाहे जितनी कोशिश की जाए, वह परवान नहीं चढ़ सकती है, जब तक इन विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में समस्या की गहराई और उससे जुड़ी संवेदना नहीं जागती।

भारत के तमाम महानगरों में यातायात, वर्षा जल निकासी और कचरा निपटान की समस्या एक जैसी है। डब्लूआरआइ इंडिया की एक शोध परियोजना के शुरुआती निष्कर्षो से मालूम होता है कि भारत के दस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और बंगलुरु) में 2000-2015 (शहर के केंद्र के दस किमी के भीतर) के बीच हुए नए नगरीय विकास कार्यों के तहत बनी 35 फीसद इमारतों का निर्माण (428 वर्ग किमी) भूजल पुनर्भरण की अधिक या अत्यधिक संभावना वाले निचले इलाकों में हुआ है। ये सभी शहर कई वर्षों से बाढ़ या डूब जैसी समस्या से जूझते नजर आते हैं।

इस साल गर्मी ने पिछले सारे रेकार्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात और गर्मी के मिजाज में बदलाव हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि एक महीने या पूरे ऋतु में जितनी औसत बरसात होनी थी वह एक या कुछ दिनों में ही हो गई। जैसे दिल्ली में 28 जून की एक हा जन को एक ही दिन में में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 1235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जाहिर है, 88 साल 24 जून, 1936 को पहले दिल्ली का रूप आज जैसा नही था। न इतने लोग थे लोग थे और न इतनी कालोनियां थीं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 128 जून का को हुई बारिश में दिल्ली में पचास जगहों पर पर विकट जलभराव के हालात देखे गए। जलभराव से निपटने के लिए दिन भर संबंधित विभागों की टीमें लगी तक भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया। पिछले साल आज रहीं. लेकिन शाम तक दिल्ली में में आई बाढ़ की याद ताजा हो आई, जब लोगों के घरों में पानी घुस गया था और उन्हें बाहर तंबुओं में शरण लेनी पड़ी थी। बरसात में जलभराव से उपजी समस्याएं और ठंड तथा गर्मी में बेघरों की बड़ी तादाद में मौत होना दिल्ली के समुचित विकास की कमी को ही नहीं बयान करता, बल्कि मानवीय स्तर पर समाज में कम होती सामाजिकता और संवेदना की कमी को भी दर्शाता है। आजादी के बाद से राजधानी के रूप में दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझती रही है। जल माफिया की मनमानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और बहुत बड़े पैमाने पर झुग्गियों के रातोंरात खड़े हो जाने जैसी घटनाएं दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी और शहर के रूप में। पहचान बनाने से रोकते रहे हैं। हर साल सर्दी और बरसात में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू, चिकनगुनिया, मौसमी बुखार, मलेरिया से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जलभराव की वजह से इन बीमारियों का फैलाव तेजी से होता है। इसलिए दिल्ली को समस्या मुक्त राजधानी के रूप में विकसित करने की जरूरत है।

जलभराव और अतिक्रमण के अलावा कूड़े-कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम महज सरकार से नहीं होगा। आम आदमी को भी अपनी आदतों, लापरवाही और गैर-जिम्मेदराना हरकतों को छोड़ना होगा। कम क्षेत्रफल में ज्यादा आबादी का बोझ ढो रही दिल्ली में हर वर्ष बढ़ते लाखों वाहन भी दिल्ली की मौजूदा सड़कों और यातायात व्यवस्था की मौजूदा हालात को बदतर करने के जिम्मेदार हैं जलभराव से ठप यातायात या जाम के हालात सड़क की क्षमता से बहुत ज्यादा वाहनों की वजह से पैदा होते है। इसलिए व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल की जगह सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग। बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जाम की वजह से दिल्ली में पर्यावरण की समस्या खतरनाक स्तर तक पहुंच पहुंच जाती है । इसलिए सड़क यातायात व्यवस्था, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली वालों को भी आगे आना होगा। फिर, दिल्ली की समस्याओं को दलगत भावना से ऊपर उठ कर देखने की जरूरत है। जब तक यह भावना नहीं आएगी कि दिल्ली हमारी है और इसकी हर समस्या को हल करने में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है तब तक दिल्ली को दुनिया की सर्वोत्तम राजधानी के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।

भारत की मजबूत बुनियाद को बताता है आर्थिक वृद्धि परिदृश्य

परिवहन विशेष न्यूज

गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत हो सकती है। यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने अगस्त में आरबीआई के चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य से नीचे 3.65 प्रतिशत पर रही।

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत का आर्थिक वृद्धि परिदृश्य देश के वृहद आर्थिक बुनियाद की मजबूती को बताता है। उन्होंने कहा कि इसमें निजी उपभोग और निवेश जैसे घरेलू तत्व प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ब्रेटन वुड्स कमेटी, सिंगापुर द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण आए गंभीर संकट से उबर गई और इसकी 2021-24 के दौरान औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रही।

चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी यानी आधार मूल्य पर वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दास ने मुद्रास्फीति के बारे में कहा कि यह अप्रैल, 2022 के 7.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर दो से छह प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में आ गई है, लेकिन 'हमें अभी भी एक दूरी तय करनी है और हम दूसरी तरफ देखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत हो सकती है। यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा, 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने अगस्त में आरबीआई के चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य से नीचे 3.65 प्रतिशत पर रही। जुलाई में यह पांच साल के निचले स्तर 3.60 प्रतिशत पर थी।

मध्यम अवधि में सार्वजनिक ऋण का स्तर घट रहा

उन्होंने कहा, 'राजकोषीय मजबूती जारी है और मध्यम अवधि में सार्वजनिक ऋृण का स्तर घट रहा है। कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जिससे उनके कर्ज में कमी आई है और लाभ के कारण मजबूत वृद्धि संभव हुई है।' गवर्नर ने कहा कि आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बहीखाता भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा हमारे परीक्षणों से पता चलता है कि ये वित्तीय इकाइयां गंभीर तनाव परि2श्यों में भी नियामकीय पूंजी और नकदी आवश्यकताओं को बनाए रखने में सक्षम होंगी।'

अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है भारत का दृष्टिकोण दास ने कहा कि वैश्विक प्रगति के बारे में भारत का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है जो लोगों पर केंद्रित, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता और उसके बाद उसका निरंतर योगदान नयी दिल्ली के विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' बनाने के दृष्टिकोण को बताता है।

दास ने कहा, 'इन प्राथमिकताओं में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) को मजबूत करना, डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋृण का समाधान और भविष्य के शहरों का वित्तपोषण करना आदि शामिल है।

क्या अभी कम नहीं होगी आपकी ईएमआई ? जानिए आरबीआई गवर्नर ने क्या दिया

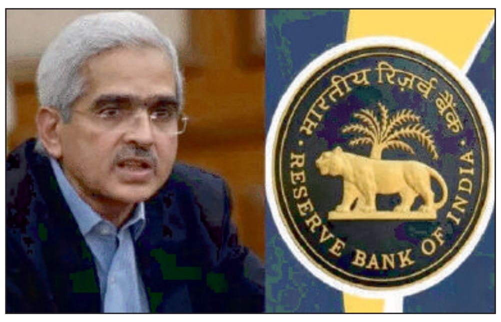

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में उतार-चढ़ाव के आधार पर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 3.65 प्रतिशत रही। इससे यह लगातार दूसरा महीना रहा जब मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से कम रही। सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के घटबढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। इससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती से जुड़े फैसले लेने में आसानी होती है।

नई दिल्ली। अमेरिका में महंगाई से मुद्रास्फीति में राहत के बाद ब्याज दरों में कटौती का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। बस देखने वाली बात यह होगी कि फेडरल रिजर्व नीतिगत ब्याज दरों में कितनी कटौती करता है। भारत में मुद्रास्फीति काबू में दिख रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कोई कटौती करके कर्ज लेना सस्ता करेगा या नहीं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति कम होने पर खुशी जताई है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी महंगाई करने पर फोकस करने की जरूरत है। ब्रेटन वुड्स कमेटी द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में मुख्य भाषण में दास ने कहा, ₹मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत पर थी, जो वहां से घटकर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास आ गई है। लेकिन, हमें अभी भी काफी दूरी तय करनी है और हम दूसरी तरफ देखने का जोखिम नहीं उठा सकते।₹

आरबीआई के अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत हो जाएगी। गवर्नर ने आगे कहा कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि और व्यापार ने बड़े पैमाने पर नकारात्मक जोखिमों को झेला है, लेकिन मुद्रास्फीति का अंतिम पड़ाव चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, जिससे वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं।

दास ने कहा, ₹वैश्विक मुद्रास्फीति की गति धीमी हो रही है। इससे मौद्रिक नीति को आसान बनाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।₹ उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति प्रबंधन विवेकपूर्ण होना चाहिए। सरकार को भी सप्लाई के मोर्चे पर सजग रहना होगा। दास ने कहा कि दरों में कटौती की बाजार उम्मीदें अब गति पकड़ रही हैं। खासकर यूएस फेड से नीतिगत बदलाव के संकेतों के बाद।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कई ऐसे केंद्रीय बैंक भी हैं जो स्वाभाविक और उचित तरीके से अपने देशों में मुद्रास्फीति पर पूरी तरह से लगाम लगने से पहले नीति में समय से पहले ढील देने के खिलाफ हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन देशों के केंद्रीय बैंकों को अपने घरेलू मुद्रास्फीति-विकास संतुलन पर नजर रखने और नीतिगत विकल्प बनाने की जरूरत है।

आरबीआई गवर्नर के रुख से लगता है कि अभी केंद्रीय बैंक का जोर महंगाई को कम करने पर ही है। ऐसे में हो सकता है कि आरबीआई फिलहाल नीतिगत ब्याज दरों में कटौती से परहेज करे।

दुनियाभर में कैसे तय होता है सोने का दाम, क्या है कीमतों में उतार-चढ़ाव के पीछे की वजह?

गोल्ड प्राइस सोने के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। आगामी फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी खरीद में तेजी आएगी ऐसे सें कीमती धातु के उतार-चढ़ाव को लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर सोने की कीमत में बदलाव क्यों होता है।

नई दिल्ली। अक्टूबर महीने से फेस्टिव सीजन (Festive Season 2024) का आगाज हो जाएगा। इस आगाज के साथ ही गोल्ड की खरीद में भी तेजी देखने को मिल सकती है। जब भी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से सोने के भाव (Gold Price) जरूर पूछते हैं। ऐसे में हम अक्सर देखते होंगे कि सोने की कीमत में रोजाना थोड़ा बदलाव होता है। हो सकता है आज और कल की कीमत में 200 रुपये का अंतर हो।

ऐसे में मन में सवाल आता कि आखिर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों आता है और इसकी कीमत कौन तय करता है। हम आपको इस आर्टिकल में इसी प्रकार के सवालों का जवाब देंगे।

कैसे तय होता है सोने की कीमत

देश के किस शहरों में कितने रुपये का सोना मिलेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ज्वेलर्स किस भाव पर सोना खरीद रहा है। ज्वेलर्स जिस भाव पर गोल्ड खरीदते हैं उसे स्पॉट रेट यानी हाजिर भाव कहा जाता है। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड किस भाव पर ट्रेड कर रहा है उस आधार पर ही स्पॉट प्राइस तय किया जाता है।

MCX पर कैसे तय होती है सोने की कीमत

अब सवाल आता है कि MCX पर सोने की कीमत कैसे तय होती है। एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमत को तय करने के पीछे कई कारक हैं। भारतीय बाजारों में गोल्ड डिमांड, सप्लाई के आंकड़ें और ग्लोबल मार्केट में महंगाई को ध्यान में रखकर ही गोल्ड की कीमत और अन्य धातु की कीमत तय होती है।

एमसीएक्स पर सोने की कीमत तय करने से पहले लंदन स्थित बुलियन मार्केट एसोसिएशन से को-ऑर्डिनेशन किया जाता है। इसके बाद ही गोल्ड प्राइस तय होती है। हालांकि एमसीएक्स पर जो गोल्ड प्राइस शो होता है उसमें वैट, लेवी एवं लागत भी शामिल होता है।

गोल्ड की कीमत पर पड़ता है किन चीजों का असर

गोल्ड की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर कई कारकों का असर पड़ता है। इसमें सबसे मुख्य आर्थिक और राजनीतिक फैसले हैं। जी हां, अगर ग्लोबली कोई बड़ा फैसला या फिर घटना होता है तो इसका असर गोल्ड पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर रुस और यूक्रेन के युद्ध के समय में गोल्ड की कीमतो में शानदार तेजी आई थी।

भारत और दुनिया में कैसे तय होता है सोने के दाम

अगर सोने की कीमतों की बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा कि दुबई में सोना सस्ता है। ऐसे में सवाल है कि भारत या फिर बाकी देशों में सोने की कीमत किस आधार पर तय होती है। इसका जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी बुलियन मार्केट ही गोल्ड की कीमत को तय करती है।

पेंशनभोगी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाक विभाग उठा रहा बड़ा कदम

परिवहन विशेष न्यूज

डाक विभाग बुजुर्ग पेंशनभोगियों को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने में मदद के लिए उनके घर तक सेवाएं पहुंचाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 1-30 नवंबर 2024 तक पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का फैसला लिया है। 2023 में 1.45 करोड़ पेंशनभोगियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे।

नई दिल्ली। बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) दाखिल करने में मदद करने के लिए डाक विभाग उन्हें उनके घर पर सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने एक से 30 नवंबर, 2024 तक देशभर के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान आयोजित करने का फैसला किया है।

सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 का प्रारूप तय करने के लिए 12 सितंबर, 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने डाक सेवाओं के महानिदेशक संजय शरण, डाक विभाग के उपमहानिदेशक राजुल भट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी व सीईओ आर. विश्वेशरन व अन्य के साथ बैठक की थी।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, जिला डाकघरों पर डीएलसी अभियान 3.0 के आयोजन के लिए ये डाकघर पेंशनभोगी कल्याण संघों, पेंशन वितरित करने वाले बैंकों, यूआइडीएआइ व अन्य के साथ समन्वय करेंगे। इसके अनुसार, 'जीवन प्रमाण (या डीएलसी) एंड्रायड स्मार्ट फोन से फेस आथेंटिकेशन के जरिये जिला डाकघरों पर पेंशनभोगियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है।' साथ ही कहा है, "डाक विभाग बुजुर्गों को उनके घर तक सेवाएं भी पहुंचाएगा तथा पेंशनभोगियों को आवश्यकतानुसार डीएलसी जमा करने के लिए सूचित करेगा।"

बयान के अनुसार, डीएलसी 3.0 अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बैनर्स, इंटरनेट मीडिया, एसएमएस एवं शार्ट वीडियो के जरिये व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसमें यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि 2023 में डीएलसी अभियान 2.0 का आयोजन सौ शहरों में किया गया था और 1.45 करोड़ पेंशनभोगियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे।

आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी, एगोरा एडवाइजरी से पैसा... सेबी चीफ ने सभी आरोपों पर दी सफाई

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सेबी चीफ माधबी पुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने 11 सितंबर को बुच की 'अनुचित व्यवहार हितों के टकराव और सेबी के सदस्य के रूप में काम करते हुए कंपनियों से भुगतान स्वीकार करने' के आरोपों को लेकर 'चुप्पी' पर सवाल उठाया था। अब सेबी चीफ ने आरोपों पर जवाब दिया है।

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धवल बुच और भारत में अगोरा एडवाइजरी एवं सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम की फर्मों के कंसल्टिंग असाइनमेंट्स के बारे में सवाल उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के जीवनसाथी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसके लिए पेशेवर योग्यता से अलग हटकर दूसरी चीजों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है। ऐसी धारणाएं योग्यता और विशेषज्ञता की ताकत को नजरअंदाज करती हैं और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"

माधबी पुरी बुच और धवल बुच, संयुक्त बयान में

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने अपने खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज किया है। सेबी चीफ ने आज (13 सितंबर) अपने पति धवल बुच के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें बुच दंपती का कहना है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं किया है और न ही किसी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने सभी हालिया आरोपों को 'पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक' करार दिया है।

सेबी चीफ के खिलाफ क्या हैं आरोप?

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सेबी चीफ बुच के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें खासकर अगोरा एडवाइजरी की चर्चा है, जिसमें कथित तौर पर बुच की 99 फीसदी हिस्सेदारी है। बुच पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने पूर्व नियोक्ता ICICI बैंक और महिंद्रा ग्रुप को पैसों के बदले अनुचित फायदा पहुंचाया।

कांग्रेस का दावा है कि माधबी पुरी ने एगोरा के जरिए 2.95 करोड़ रुपये कमाए हैं। ये रकम महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, पिडीलाइट, आईसीआईसीआई, सैम्बकॉर्प और विसूलीजी एंड फाइनेंस इन 6 कंपनियों से कमाई गई। ये सारी लिस्टेड कंपनियां सेबी से रेगुलेट होती हैं और साथ ही एगोरा की क्लाइंट भी हैं।

कांग्रेस ने बुच पर माधवी पर SEBI से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, ICICI ने आरोपों को नकारते हुए कहा था कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ रिटायरमेंटल बेनिफिट्स लिए।

वहीं, ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एक बयान में कहा था कि धवल को उनकी योग्यता की वजह से कंपनी में नियुक्त किया था। हमने कभी भी सेबी से किसी तरह के सहूलियत नहीं मांगी थी। कांग्रेस का दावा था कि धवल बुच को महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) से 2019 और 2021 के बीच 4.78 करोड़ रुपये मिले थे।

आरोपों पर क्यों बोलीं माधबी पुरी

अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने 11 सितंबर को बुच की 'अनुचित व्यवहार, हितों के टकराव और सेबी के सदस्य के रूप में काम करते हुए कंपनियों से भुगतान स्वीकार करने' के नए आरोपों को लेकर 'चुप्पी' पर सवाल उठाया था।

हिंडनबर्ग ने ही सबसे पहले सेबी चीफ की गतिविधियों पर सवाल उठाया था। उसी के बाद सेबी चीफ माधबी पुरी बुच का जवाब आया है। बुच दंपती ने अपने बयान में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप 'झूठे, गलत और दुर्भावनापूर्ण' से प्रेरित हैं।

बयान में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिडिलाइट, डॉ. रेड्डीज और अल्वारेज एंड मार्सल जैसी कंपनियों के साथ धवल बुच के एडवाइजरी वर्क का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अनुबंध पूरी तरह से योग्यता आधारित थे और माधबी पुरी बुच के सेबी चीफ बनने से काफी पहले हुए थे।

बुच ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व नियोक्ता ICICI Bank से जुड़े किसी भी रेगुलेटरी मामले को नहीं निपटाया है। कई लिस्टेड कंपनियों के साथ हितों के टकराव के मसले पर माधबी पुरी ने कहा कि सेबी से जुड़ने के बाद उन्होंने किसी भी स्तर पर कभी भी एगोरा एडवाइजरी, एगोरा पार्टनर्स, महिंद्रा ग्रुप, पिडिलाइट, डॉ. रेड्डीज, अल्वारेज एंड मार्सल, सेम्बकॉर्प, विसु लीजिंग या आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) से जुड़ी किसी भी फाइल को नहीं निपटाया है।

मिलावटी मिठाई बेचने वालों की खैर नहीं, नकेल कसने के लिए FSSAI करेगा इंतजाम

त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादा खपत होने के कारण मिलावटी मिठाईयों की बाजार में भरमार होती है। आम लोगों के लिए असली-नकली का फर्क करना पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस पर नकेल कसने के लिए FSSAI ने तगड़ा इंतजाम कर लिया है। जिससे मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी। बाजारों में मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाकर गुणवत्ता जांच करने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली। त्यौहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों पर नकेल कसने के लिए फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के फुड सेफ्टी कमीश्नर, सभी क्षेत्रीय निदेशकों और सभी केंद्रीय लाइसेंसिंग अथोरिटी को भेजे पत्र में अपने-अपने क्षेत्र में बाजार में मोबाइल टेस्टिंग वैन को तैनात करने और दुकानों बिकने वाले खाद्य उत्पादों का नियमित परीक्षण करने को कहा है।

एफएसएसएआई की ओर जारी निर्देश के अनुसार त्यौहारी सीजन में मिठाइयों के साथ-साथ खोआ, पनीर, घी जैसे दुग्ध उत्पादों की खपत काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और जनता को मिलावटी सामान बेच देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका निगरानी है। इसके लिए इन सामानों के उत्पादन और बिक्री केंद्रों पर गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाना जरूरी है।

इसके साथ ही एफएसएसएआई ने मिलावटखोरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए खुफिफा तंत्र के इस्तेमाल और उनके द्वारा मिली जानकारी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। एफएसएसएआई ने इस निर्देश को अतिमहत्वपूर्ण बताते हुए इसपर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

स्थानीय सड़क सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएं
सोशल मीडिया और सटीक जानकारी का अद्वितीय उदाहरण

परिवहन विशेष न्यूज

13 सितंबर को, फरीदाबाद के मथुरा रोड पर एक टैक्सी गलत दिशा में तेज़ी से आ रही थी। एक सतर्क यात्री ने तुरंत टैक्सी को रोक कर इसका वीडियो बना लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों तक पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप, कुछ ही मिनटों में उस टैक्सी पर पोस्टल चालान जारी कर दिया गया।

यह घटना सोशल मीडिया और सटीक जानकारी की ताकत का जीवंत उदाहरण है, जो सड़क सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। बिना किसी देरी के सही कार्रवाई होने से यह स्पष्ट होता है कि यदि सही जानकारी और जागरूकता फैलती है, तो नागरिकों के छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आइए हम सभी अपने आस-पास की सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और ऐसे गलत कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि यदि हम सच्चाई के साथ सटीक जानकारी साझा करते हैं, तो स्थानीय प्रशासन भी त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होता है।

स्थानीय सड़क सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने का समय आ गया है। सोशल मीडिया को एक सशक्त माध्यम बनाएं, सटीक और प्रामाणिक जानकारी साझा करें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

- roadsafetysquad@gmail.com

ROAD SAFETY OMNI FOUNDATION (RE...
@Rsofbd2012

Caught in broad daylight on Mathura Road, taxi drivers show no concern for road safety with rampant violations. This reckless behavior endangers lives. We need stricter enforcement to ensure safer roads.

Dt. 13.09.2024

@FBDPolice @DC_Faridabad

12:53 pm · 13 Sep 24 · 21 Views

पर्यावरण पाठशाला : प्रकृति से दूर होते आधुनिक जीवन के कड़वे सच : अंकुर

आजकल हम अक्सर एक-दूसरे से सुनते हैं, "मौसम बड़ा खराब है।" और ये सच भी है। जब बारिश होती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि ऑफिस में बिना एयर कंडीशनिंग के रहना मुश्किल हो जाता है, और दिल्ली एनसीआर में पेड़-पौधों की हालत तो दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम अपनी जड़ें भूलते जा रहे हैं। एक वक्त था जब हमारे आसपास हरियाली और प्राकृतिक पेड़-पौधे होते थे, पर अब हमने उन्हें 'डिज़ाइनर ट्रीज़' से बदल दिया है। ये पेड़ दिखने में भले ही आकर्षक हों, लेकिन न तो ये पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं और न ही हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। देशी पेड़ों की जगह अब विदेशी किस्मों ने ले ली है, जो न हमारी मिट्टी के अनुरूप हैं और न हमारे मौसम के।

गर्मी के मौसम में हम एयर कंडीशनर के बिना रह नहीं पाते, जबकि एक समय था जब पेड़ों की छांव ही हमारी सबसे बड़ी राहत थी। हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने काम में, कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि प्रकृति हमें कितनी जरूरी चीजें मुफ्त में देती थी – ताजी हवा, स्वच्छ पानी और सुकून देने वाली हरियाली।

सर्दी आते ही हम सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचते हैं कि क्या ये सर्दी और गर्मी असामान्य होती जा रही हैं? जलवायु परिवर्तन की यह स्थिति भी कहीं न कहीं हमारी प्रकृति से दूरी का ही परिणाम है।

कभी-कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है – हम जी रहे हैं या सिर्फ कमाने के चक्कर में अपनी ज़िन्दगी से दूर हो रहे हैं? हम जितना आधुनिक जीवन जीने के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही हम खुद को प्रकृति से दूर कर रहे हैं। वो सुखद पल, जब बारिश में भीगकर हम खुश होते थे, या जब पेड़ों के नीचे बैठकर सुकून पाते थे, वो कहीं खो गए हैं।

आधुनिकता के इस दौड़ में हम वो सब कुछ खो रहे हैं, जो हमें असल में इंसान बनाए रखता था। अब वक्त आ गया है कि हम रुकें, सोचें और खुद से ये सवाल करें – क्या हम वास्तव में प्रकृति से इतने दूर चले गए हैं कि अब हमें उसकी कोई परवाह नहीं रही? और अगर हां, तो क्या हम इस खोई हुई कड़ी को फिर से जोड़ सकते हैं?

क्योंकि असल में प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं।

indiangreenbuddy@gmail.com

भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 20 किलो सोना जब्त

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 20 किलो सोना जब्त। सीटी और जीएसटी ने मुंबई से आ रही इंडिगो फ्लाइट से सोना जब्त किया। इस मामले में कुछ कारोबारियों से पूछताछ की गई है।20 किलो सोने से 16 किलो सोने की गणना सही है जबकि 4 किलो सोने की गणना मेल नहीं खाती। संबंधित व्यापारियों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है।यह सोना भुवनेश्वर के 5 व्यापारी लेकर आए थे जबकि बताया जा रहा है कि यह सोना कालाहांडी और अनुगोल इलाके के व्यापारियों के पास जा रहा था।

कुछ सूत्रों से खबर मिली कि मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट में सीटी और जीएसटी सोना आ रहा है। बाद में सीटी व जीएसटी की टीम बाहर ही रह गयी एयरपोर्ट से निकलते वक्त एक शख्स 20 किलो सोना लेकर सीटी और जीएसटी टीम में बैठ गया। वलबिहार में सीटी और जीएसटी कार्यालय में एक जांच की गई। 20 किलो सोने से 16 किलो सोने की गणना सही थी जबकि 4 किलो सोने की गणना मेल नहीं खा रही थी। सीटी और जीएसटी टीम ने खुदाई शुरू कर दी है। सीटी जीएसटी ने कहा कि जांच जारी है जबकि सोना राजस्थान से आया था।

सीटी और जीएसटी ने 26 तारीख को भुवनेश्वर हवाई अड्डे से 300 किलो सोना, 2000 किलो रुपये जब्त किए। निरीक्षण के बाद कुछ व्यापारियों को नोटिस दिया गया। जांच अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि मानसून का मौसम होने के कारण व्यापारी व्यापार के लिए अधिक सोना ला रहे हैं।

मात्र 25 टन वजन, परीक्षण में जमकर बरसाए गोले; चीनी सीमा पर दिखेगा जोरावर टैंक का दम

परिवहन विशेष न्यूज

डीआरडीओ ने जोरावर टैंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मात्र 25 टन वजनी हल्के टैंक चीन के साथ सीमा पर सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये टैंक हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम है। इनके प्रदर्शन का कठोरता से मूल्यांकन किया गया और इसने सभी निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता के साथ गोले बरसाए।

नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को मात्र 25 टन वजनी हल्के टैंक जोरावर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान टैंक ने निशाने पर जमकर गोले बरसाए और सभी इच्छित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए असाधारण प्रदर्शन किया। इसे चीन के साथ सीमा पर सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

यह एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और एलएंडटी डिफेंस वायु-परिवहन योग्य टैंक विकसित कर रहा है, जिसे चीन सीमा पर तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षणों को रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

प्रारंभिक परीक्षण रहा सफल

रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'डीआरडीओ ने 13 सितंबर को जोरावर का सफलतापूर्वक प्रारंभिक परीक्षण किया, जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम है। टैंक के प्रदर्शन का कठोरता से मूल्यांकन किया गया और इसने सभी निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता के साथ गोले बरसाए। भारतीय सेना 350 से अधिक हल्के टैंक तैनात करने पर विचार कर रही है। अधिकांश की तैनाती पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में की जाएगी।'

गौरतलब है कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से सेना ने लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश सहित एलएसी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से परिवहन योग्य एम-777 अल्ट्रा लाइट हावित्जर तोपों की तैनाती की है। पूर्वी लद्दाख में टी-90 और टी-72 जैसे भारी टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को भी तैनात किया है।

कक्षाओं में होंगे तंबाकू मॉनीटर, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

युवाओं में तंबाकू के इस्तेमाल की बढ़ती लत को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का एक अभियान छेड़ा है। साथ ही इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू की किसी भी रूप में बिक्री प्रतिबंधित होगी।

नई दिल्ली। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तंबाकू का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना अब छात्रों को भारी पड़ सकता है, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लग सकता है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा में अब एक तंबाकू मॉनीटर की तैनाती की जाएगी, जो उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से ही कोई होगा। स्कूलों में यह नियुक्ति कक्षा नौ के बाद की कक्षाओं में दी जाएगी। इस दौरान तंबाकू मॉनीटर कक्षा में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले साथियों पर न सिर्फ नजर रखेगा, बल्कि इसकी जानकारी स्कूल या संस्थान के स्तर पर नियुक्ति तंबाकू मॉनीटर टीचर को देगा, जो बाद में आगे की कार्रवाई करेगा।

जारी की विस्तृत गइडलाइन : युवाओं में तंबाकू के इस्तेमाल की बढ़ती लत को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का एक अभियान छेड़ा है। साथ ही इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू की किसी भी रूप में बिक्री प्रतिबंधित होगी।

शैक्षणिक संस्थानों ने यह दूरी निर्धारित करने के साथ उसके आसपास तंबाकू प्रतिबंध का बोर्ड लगाने को भी कहा गया है। गाइडलाइन में शैक्षणिक संस्थानों से सभी प्रमुख स्थानों यानी गेट, असेंबली ग्राउंड, खेल के मैदान आदि में तंबाकू मुक्त क्षेत्र या तंबाकू प्रतिबंधित क्षेत्र से जुड़े बैनर-पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए है।

दो दिन में 750 अधिकारी मिलकर तैयार करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का रोडमैप, अमित शाह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन

राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए नेशनल सेक्योरिटी स्ट्रेटिजीज कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दो दिन तक फिजीकल और वर्जुअल दोनों मोड में चलने वाले सम्मेलन में 750 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं जो रोडमैप तैयार करने का काम करेंगे।

नई दिल्ली। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए नेशनल सेक्योरिटी स्ट्रेटिजीज कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। सम्मेलन में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सुरक्षा से जुड़े अत्याधुनिक तकनीक (कटिंग एज टेक्नोलाजी) पर काम करने वाले युवा पुलिस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

दो दिन तक फिजीकल और वर्जुअल दोनों मोड में चलने वाले सम्मेलन में 750 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तेजी से बदलती तकनीक के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां भी बदल रही हैं और इसके अनुरूप सुरक्षा एजेंसियों को तैयार करना जरूरी है।

पीएम मोदी ने दिया था सुझाव

इसे देखते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों के सालाना सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने का रोडमैप तैयार करने के लिए हाईब्रिड मोड में नेशनल सेक्यूरिटी स्ट्रेटिजीज कांफ्रेंस का सुझाव दिया था, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए।

गृह मंत्री ने डैशबोर्ड का भी किया उद्घाटन

सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किये गए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड को पुलिस महानिदेशकों के सालाना कांफ्रेंस में लिए गए फैसलों की अलम पर रियल टाइम जानकारी के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन फैसलों को कितना-कितना अमल किया जा सका है, पूरी जानकारी इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। इसमें सालों से अमल में नहीं लाये जा सके फैसलों की भी जानकारी होगी।

दिल्ली में 'स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता' 2024 अभियान का शुभारंभ, केंद्र का दो लाख से ज्यादा गंदी जगहों को बदलने का लक्ष्य

देश की केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वर्ष स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर लगभग दो लाख कठिन और गंदे स्थानों को परिवर्तित करने का लक्ष्य बना रही है। स्वच्छता लक्षित एकाई (सीटीयू) इस वर्ष के अभियान का मुख्य आकर्षण है और इसमें सीटीयू की पहचान और एक पोर्टल के माध्यम से मैपिंग शामिल है।

नई दिल्ली। देश की केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वर्ष 'स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता' की थीम पर लगभग दो लाख कठिन और गंदे स्थानों को परिवर्तित करने का लक्ष्य बना रही है। स्वच्छता लक्षित एकाई (सीटीयू) इस वर्ष के अभियान का मुख्य आकर्षण है और इसमें सीटीयू की पहचान और एक पोर्टल के माध्यम से मैपिंग शामिल है। इसकी घोषणा आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित अभियान के कर्टन रेजर इवेंट में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पटिल ने की। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि केंद्रीय पीएसयू, उद्योग भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों को सीटीयू अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान में पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभयारण्यों में श्रमदान के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर मेगा स्वच्छता अभियान शामिल हैं। साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रालय और राज्य विभिन्न नागरिक जुड़ाव गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। अभियान 17 सितंबर से शुरू होने वाला है और 2 अक्टूबर, 2024, महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष का अभियान 'स्वच्छता सेवा है' से आगे बढ़कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के 'स्वभाव और संस्कार' के रूप में स्वच्छता को अपनाने का बड़ा कदम है।

कविता : अजनबी कौन हो तुम?

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

क्या, आंखों-आंखों में ही सब कहोगे?
अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगे।
मुझे समझ नहीं आया तो क्या करोगे?
तब तो मौन व्रत तोड़ोगे।

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

क्या, हाथों में हाथ ले दोगे मेरा साथ?
क्या, ऐसी भी होती है कभी मुलाकात?
ये कैसा रिश्ता है मौन में भी पिसता है?
क्या तू कोई फरिश्ता है?

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

कविता : 84 के परम मित्र

84 के परम मित्र।

पैरा ओलंपिक गेम्स की बात ही निराली है,
ये पदकवीर घर पर लौटे लगता दिवाली है।

पेरिस से पदक ले आए खूब जीत कर,
इन्होंने की हैं मेहनत भी खूब डटकर।

भारत देश का था 84 सदस्यों का दल।
ले आया 29 पदक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर।

7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक,
इन खिलाड़ियों ने किया प्रयास अथक।

तीन साल पहले टोक्यो में हासिल हुए 19
पिछले प्रदर्शन को छोड़ पीछे श्रेष्ठ हुए 20

वीरों को आवास बुला सम्मानित करवाएँ,
ये ऐसे प्रधानमंत्री जो परम मित्र कहलाए।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
31, संजय नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023